राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 9 जून • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य उसका नहीं होता, मूल्य होता है उसकी लौ का जिसे कोई अंधेरा, अंधेरे के तरकश का कोई तीर ऐसा नहीं जो बुझा सके।

-विष्णु प्रभाकर

अधिकारों का प्रयोग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग के आरोप में लिखे लेख पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में धांधली के दावों को खारिज किया। कहा कि अनुकूल चुनाव परिणाम न मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना बेतुका है। गांधी के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्ल्यूप्रिंट था, जो बिहार में होने वाले चुनाव में भी दोहराया जाएगा। उन्होंने लिखा, मैच फिक्स किए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर हैं। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है, वह भले ही जीत जाए मगर इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता

है। आयोग ने अपने बयान में कहा, कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम और लाखों कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है। राहुल ने आयोग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा-आप संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर वाले, टालमटोल वाला नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। हालांकि राहुल को आरोपों के पुख्ता सबूत देने के प्रयास भी करने चाहिए। महाराष्ट्र के मतदाताओं में 8% की वृद्धि पर कांग्रेस ने उसी वक्त आपत्ति दर्ज की थी। सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनाव में करारी हार को विपक्ष गले नहीं उतार पा रहा। इसलिए आरोप गढ़ कर मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय होने के बावजूद मोदी सरकार के विभिन्न निर्णयों के बाद कई मौकों पर विवादों में आता रहा है। स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव का दारोमदार अंततः आयोग पर होता है। मगर पूर्व में चुनाव आयुक्त रह चुके सुकुमार सेन, टीएन शेषन और जेएम लिंग्दोह की तरह कोई भी संस्था की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने में सफल नहीं हो सका। बात भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक भाषणों की हो, इलेक्टोरल बॉन्ड या वोट संख्या की बजाय प्रतिशत जारी करने की, बार-बार आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगा जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उसे पक्षपाती नहीं होना चाहिए। नियमों की अनदेखी या उपेक्षा पर सभी दलों को फटकार लगाने और जवाबतलबी में संकोच नहीं करना चाहिए। राजनेताओं के तरीके बदल रहे हैं। वे वोट के लोभ में असंवैधानिक और निंदनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वोट प्राप्ति के लिए दांव-पेंच करते हैं जिस पर आयोग को कड़ी आपत्ति करनी चाहिए।

विवेक ही कारगर

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई का यह कहना कि न्यायिक निर्णय लेने में प्रौद्योगिकी को मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं लेना चाहिए अत्यंत विचारणीय तथ्य है, प्रौद्योगिकी मानव मस्तिष्क का स्थान भला कैसे ले सकती है जबकि उसकी भूमिका सहायक से अधिक नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति गवई लंदन विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (एसओएएस) में 'भारतीय कानूनी प्रणाली में प्रौद्योगिकी की भूमिका' विषय पर आयोजित व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उनका यह कहना बिल्कुल उचित

है कि स्वचालित वाद सूचियों, 'डिजिटल कियोस्क' और आभासी सहायकों जैसे नवाचारों का स्वागत किया जा सकता है। पर विवेक, सहानुभूति और न्यायिक व्याख्या बेशकीमती हैं। प्रौद्योगिकी इनका स्थान कभी नहीं ले सकती। भारत के पास तकनीकी दक्षता, दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक जनादेश है, जिससे समानता, सम्मान और न्याय के हमारे मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाली प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं। प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण करते ही न्यायमूर्ति गवई ने न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग पर उच्चतम न्यायालय के अनुसंधान और योजना केंद्र के साथ चर्चा की शुरुआत की थी। प्रधान न्यायाधीश की इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रहा जा सकता कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय विवेक का स्थान लेने के लिए न किया जाए। हालांकि कुछ मामलों में न्यायपालिका ने प्रौद्योगिकी को अपनाना शुरू किया है, लेकिन एआई के इस्तेमाल के मामले में केस प्रबंधन से लेकर कानूनी अनुसंधान, और दस्तावेज के अनुवाद तक भरपूर सावधानी जरूरी है। दुनिया भर में कानूनी प्रणालियों में एआई के नैतिक उपयोग पर गंभीर बहस चल रही है। एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, गलत सूचना, आंकड़ों में हेरफेर और गोपनीयता जैसे मामलों ने सबकी चिंता बढ़ाई हुई है। पीड़ित की पहचान उजागर होने का खतरा भी बना रहता है। इस मामले में स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं है। दूसरे, एआई उपकरणों के उचित विनियमन और निगरानी के अभाव में वे मनगढ़ंत उद्धरण या पक्षपातपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। न्याय तक पहुंच केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक साझा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। सुलभ, पारदर्शी और समावेशी न्याय सबकी जरूरत है।

बिरसा मुंडा पुण्यतिथि/आर.के. जैन

जनजातीय गर्जना का नाम

जैसे जंगल की आग अनायास भड़क उठती है, और वृक्षों को अपने आगोश में ले लेती है, वैसे ही एक साधारण आदिवासी बालक ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला कर रख दी थी। वह बालक था आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा। उनकी पुण्यतिथि, 9 जून केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस अमर बलिदान का प्रतीक है, जिसने आदिवासी अस्मिता को नई रोशनी दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अनछुआ अध्याय जोड़ा।

15 नवम्बर, 1875 को झारखंड के उलीहातु गांव में मुंडा जनजाति के एक साधारण परिवार में जन्मे बिरसा का जीवन संघर्षों की भट्ठी में तपा था। उनके पिता सुगना मुंडा और माता करमी हातु ने उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम और संस्कारों की नींव डाली। उस दौर में अंग्रेजी शासन ने आदिवासियों की दुनिया को उजाड़ दी थी। जमींदारी प्रथा ने उनकी पुश्तैनी जमीनें छीन लीं, जंगल, जो उनकी आत्मा का हिस्सा थे, अंग्रेजों और जमींदारों के कब्जे में चले गए। ईसाई मिशनरियों ने उनकी सांस्कृतिक जड़ों पर प्रहार किया, और आदिवासियों को उनकी ही धरती पर पराधीन बना दिया गया। इन अंधेरी परिस्थितियों में बिरसा ने शोषण की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया। सबसे पहले सामाजिक सुधार का बीड़ा उठाया। 'बिरसाइत' धर्म की स्थापना कर उन्होंने आदिवासियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा। जब बिरसा ने देखा कि अंग्रेजों की नीतियां और जमींदारों की लूट आदिवासियों के अस्तित्व को ही निगल रही हैं, तो उन्होंने तीर-कमान उठा लिया। 1895 में शुरू हुआ उनका 'उलगुलान'-महाविद्रोह-ऐसी आंधी थी, जिसने झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के जंगलों को अपने रंग में रंग दिया। 'अबुआ दिशोम रे अबुआ राज' (हमारा देश, हमारा राज) का नारा उनकी हुंकार बन गया। बिरसा ने आदिवासियों को संगठित करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी। इससे ब्रिटिश शासन को बेचैन हो गया। आखिरकार, 3 फरवरी, 1900 को चक्रधरपुर में उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। रांची जेल में 9 जून, 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि यह सुनियोजित हत्या थी। बिरसा की मृत्यु भले ही शारीरिक रूप से हुई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हर उस संघर्ष में जीवित है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है।

ग्राहक हितैषी बने प्रणाली

बैंकों में कामकाज

विनीत नारायण

भारतीय बैंकिंग प्रणाली, जो देश की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, समय-समय पर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार के लिए आलोचना का विषय बनती रही है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नये दिशा-निर्देशों का ऐलान किया गया जिनसे देश भर के बैंकों में नये सेवा शुल्कों और लेन देन की सीमाओं को लेकर असमंजस की स्थिति है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन के पूर्व महासचिव थॉमस फ्रैंको ने हाल में बैंकों द्वारा ग्राहकों से अनुचित शुल्क वसूलने और आरबीआई की नीतियों के प्रभावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

फ्रैंको ने बैंकों की उन प्रथाओं पर प्रकाश डाला है, जिनके माध्यम से ग्राहक अनजाने में अतिरिक्त शुल्क और चार्जेस का बोझ उठाते हैं। उनके अनुसार, बैंक न केवल अपनी सेवाओं के लिए मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाते हैं, बल्कि ग्राहकों को अनुचित नियमों और शर्तों के जाल में भी फंसाते हैं। उदाहरण के लिए, एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क, न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता और तीसरे पक्ष के उत्पादों (जैसे बीमा) की गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) आम ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के बावजूद बैंक ग्राहकों के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने में विफल रहे हैं। वे बताते हैं कि बैंकों द्वारा लगाए गए कई शुल्क, जैसे एटीएम से नकदी निकासी पर चार्ज या न्यूनतम बैलेंस न रखने की सजा, ग्राहकों के लिए अनुचित और बोझिल हैं। विशेष रूप से छोटे बचत खाताधारकों और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

आरबीआई ने हाल में एटीएम संचालन, लेन देन सीमा और शुल्क से संबंधित नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम पर सीमित मुफ्त लेन देन की सुविधा दी जाती है, और अन्य बैंकों के एटीएम पर भी मुफ्त लेन देन की संख्या निर्धारित की गई है। इन सीमाओं को पार करने पर ग्राहकों से शुल्क वसूला जाता है। फ्रैंको का तर्क है कि ये दिशा-निर्देश बैंकों को ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की छूट देते हैं, जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से पांच मुफ्त लेन देन के बाद अतिरिक्त निकासी करता है, तो उसे प्रति लेन देन 20 रुपये तक का शुल्क देना पड़ सकता है। इसी तरह, अन्य बैंकों के एटीएम पर तीन मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क लागू होता है।

फ्रैंको के अनुसार, यह व्यवस्था ग्राहकों को उनकी ही बचत का उपयोग करने के लिए दंडित करती है। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जैसे मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अनधिकृत लेन देन की

स्थिति में ग्राहकों की शून्य देयता। हालांकि, फ्रैंको का कहना है कि इन नियमों का कार्यान्वयन अपर्याप्त है। बैंकों द्वारा ग्राहकों को सूचित करने और शिकायत निवारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बनी रहती है। थॉमस फ्रैंको ने बैंकों द्वारा तीसरे पक्ष के उत्पादों, विशेष रूप से बीमा और म्यूचुअल फंड, की मिस-सेलिंग पर विशेष ध्यान दिया है। उनके अनुसार, बैंक कर्मचारी अक्सर ग्राहकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, को भ्रामक जानकारी देकर ऐसे उत्पाद बेचते हैं, जो उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं होते। उदाहरण के लिए, सिंगल प्रीमियम बीमा पॉलिसियों की बिक्री में ग्राहकों को जोखिमों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग अपनी बचत खो देते हैं।

अक्सर देखा गया है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों को अनुचित शर्तों वाले ऋण समझौतों में फंसाया जाता है। उदाहरण के लिए, फ्लोटिंग रेट होम लोन लेने वाले ग्राहकों को ब्याज दरों में कमी का लाभ स्वचालित रूप से नहीं दिया जाता और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। यह न केवल अनुचित है, बल्कि आरबीआई के ग्राहक अधिकार चार्टर का भी उल्लंघन है, जिसमें निष्पक्ष व्यवहार और पारदर्शिता की बात कही गई है। आरबीआई ने 2014 में ग्राहक अधिकार चार्टर जारी किया था, जिसमें पांच मूलभूत अधिकारों की बात की गई थी-निष्पक्ष व्यवहार, पारदर्शिता, उपयुक्तता, गोपनीयता और शिकायत निवारण। हालांकि, फ्रैंको और अन्य उपभोक्ता कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरबीआई ने इन अधिकारों को लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उदाहरण के लिए, शिकायत निवारण के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और बैंकिंग लोकपाल अक्सर बैंकों के पक्ष में ही फैसले सुनाता है।

आरबीआई को बैंकों पर सख्ती बरतनी चाहिए और अनुचित शुल्क वसूली, मिस-सेलिंग और एकतरफा समझौतों पर रोक लगानी चाहिए। उनके अनुसार, आरबीआई की निष्क्रियता बैंकों को ग्राहकों का शोषण करने की खुली छूट देती है। बैंकों की इन प्रथाओं का सबसे अधिक प्रभाव मध्यम वर्ग, छोटे बचतकर्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों पर पड़ता है। न्यूनतम बैलेंस न रख पाने वाले खाताधारकों से भारी जुर्माना वसूला जाता है, जो उनकी बचत को और कम करता है। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं, और ग्राहकों को नुकसान की भरपाई के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

ऐसे में कुछ समाधान पर आरबीआई को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। टेलीकॉम सेक्टर की तरह बैंक खातों की पोर्टेबिलिटी को आसान करना चाहिए ताकि ग्राहक आसानी से बैंक बदल सकें। सभी शुल्क और चार्जेस की जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में देनी चाहिए। तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री के लिए सख्त नियम और ग्राहक की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। आरबीआई को शिकायत निवारण के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और बैंकों पर दंड लगाना चाहिए। छोटे लेन देन और ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम शुल्क को खत्म करना चाहिए। बैंकों द्वारा ग्राहकों से अनुचित शुल्क वसूलने और मिस-सेलिंग की प्रथाएं आम आदमी के लिए वित्तीय बोझ बढ़ा रही हैं। फ्रैंको का यह संदेश-कि 'ग्राहकों का सशक्तिकरण धन संरक्षण का सबसे सुरक्षित तरीका है,' हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बैंकिंग प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और ग्राहक-केंद्रित बनाने की जरूरत है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> कुछ समाधान पर आरबीआई को गंभीरता से विचारने की जरूरत है। टेलीकॉम सेक्टर की तरह बैंक खातों की पोर्टेबिलिटी को आसान करना चाहिए ताकि ग्राहक आसानी से बैंक बदल सकें। सभी शुल्क और चार्जेस की जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में देनी चाहिए। तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री के लिए सख्त नियम और ग्राहक की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। शिकायत निवारण के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए

कांग्रेस का बीते लोक सभा चुनावों में मत प्रतिशत 20 प्रतिशत था। राहुल गांधी को चिंता है कि मुसलमानों के समर्थन बिना उनकी पार्टी का मत प्रतिशत गिर कर 10 प्रतिशत और लोक सभा में सीटों की मौजूदा संख्या 90 से घट कर 20 से भी कम रह सकती है। उनकी राजनीति डर से प्रेरित है।

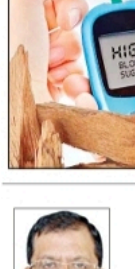

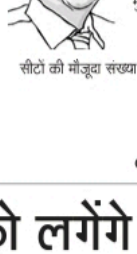

मिन्हाज मर्चेंट, पत्रकार
@MinhazMerchant

अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख

आरबीआई का निर्णय **प्रह्लाद सबनानी**

विश्व के कई देशों में भले ही आर्थिक गतिविधियों पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था नित नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के उपक्रम एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां आर्थिक विकास को गति देने में अपने प्रयास लगातार तेज किए हुए हैं। इसी क्रम में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बीती 6 जून को द्विमासिक मुद्रा नीति की अपनी घोषणा में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक, रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 6 प्रतिशत की दर से नीचे लाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है। रेपो दर उस दर को कहते हैं, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है एवं ये बैंक रेपो दर को आधार दर बनाते हुए कुछ आधार बिंदु (जमा राशि की लागत एवं लाभ की राशि का समायोजन करते हुए) जोड़ते हुए ब्याज की दर पर ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। दूसरे, भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात में सीधे ही 100 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे 4 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत की दर पर ला दिया है। इससे, बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि ऋण देने के लिए उपलब्ध हो जाएगी एवं सिस्टम में तरलता बढ़ जाएगी।

नकद आरक्षित अनुपात उस अनुपात को कहते हैं, जिस पर विभिन्न बैंकों को अपनी मांग एवं जमा देयताओं की राशि पर नकद राशि भारतीय रिजर्व बैंक पास जमा करानी होती है। अतः यह राशि इन बैंकों की पहुंच से बाहर हो जाती है एवं ऋण के रूप में इसे बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध नहीं करा सकते। यदि नकद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है तो बैंकों के पास यह राशि ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। इससे स्पष्टतः बैंकों की लाभप्रदता में सुधार होता है।

इन दोनों निर्णयों से वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत में उत्पादों की आंतरिक मांग उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी। व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण आदि सस्ते होंगे। इससे नागरिकों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने लगेगी जिसे वे अन्य पदार्थों को खरीदने में खर्च कर सकेंगे। ऋण पर ब्याज

राशि कम होने से विभिन्न उत्पादक कंपनियों की लाभप्रदता में वृद्धि होगी क्योंकि उन्हें अब बैंकों से लिए गए ऋण पर कम ब्याज देना होगा। इस कारण कंपनियां उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर विचार करेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून माह में घोषित मौद्रिक नीति का शेयर बाजार ने 6 जून को त्वरित सकारात्मक उत्तर दिया और निफ्टी एवं सेंसेक्स में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। ब्याज दरों से जुड़े क्षेत्रों विशेष रूप से बैंकिंग, रीयल एस्टेट एवं ऑटो क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला। दरअसल, अधिकतर अर्थशास्त्री रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की उम्मीद कर रहे थे परंतु रिजर्व बैंक ने 50 आधार बिंदुओं की कमी की घोषणा करते हुए आक्रामक नीति का परिचय दिया। रेपो दर में उम्मीद से अधिक कटौती से निवेशकों का भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से उन कंपानियां पर जो घरेलू मांग एवं ऋण पर निर्भर रहती हैं, पर भरोसा बढ़ा है। भारतीय कंपनियों की लाभप्रदता एवं उत्पादों की बिक्री में लगातार तेज सुधार के चलते इनकी साख अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ेगी। ये कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रूप भी ले सकती हैं। ब्याज दरों में कमी के चलते इन कंपनियों की उत्पादन लागत कम होगी जिससे इनके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

हां, रिजर्व बैंक ने अपने स्टैन्स को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल जरूर कर दिया है जिसके चलते रिजर्व बैंक रेपो दर में आगे आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ोतरी कर सकता है जबकि अकोमोडेटिव स्टैन्स में रेपो दर में केवल कमी करने की संभावना निहित रहती है। परंतु, आने वाले समय में मंहगाई की दर पर नियंत्रण, जिसकी संभावना रिजर्व बैंक ने जताई है, करने में मदद मिलेगी। इस कारण मंहगाई दर के अनुमान को 4 से घटा कर 3.70 प्रतिशत कर दिया गया है। संभव है कि रिजर्व बैंक को न्यूट्रल स्टैन्स के बावजूद रेपो दर में कमी करनी पड़े। रेपो दर एवं नकद आरक्षित अनुपात में आक्रामक कटौती को अच्छा निर्णय कहा जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में खपत एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी, उद्योग जगत अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपने पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर विचार करेगा। चूंकि भारत में मुद्रास्फीति की दर अभी नियंत्रण में है अतः रिजर्व बैंक ने विकास दर बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। हालांकि अपने स्टैन्स को न्यूट्रल रख कर मुद्रास्फीति एवं वैश्विक स्तर पर विभिन्न जोखिमों पर भी नजर बनाए रखने का संकेत दिया है। इसीलिए अर्थशास्त्री एवं बैंकिंग जगत के विशेषज्ञ इस मुद्रा नीति को क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं।

धर्मतंत्र **श्रीराम शर्मा आचार्य**

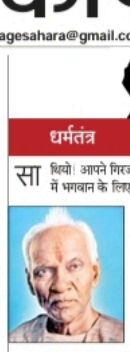

साथियो! आपने गिरजाघरों को देखा है। गिरजाघरों में भगवान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्या? वहां कहीं-कहीं मरियम की मूर्ति लगी रहती है, तो कहीं-कहीं ईसा की प्रतिमा लगी रहती है। एक छोटा-सा प्रार्थना कक्ष होता है। कहीं इसमें अस्पताल या दवाखाने वाला हिस्सा होता है। कहीं पादरियों के रहने का हिस्सा होता है। कहीं छोटा सा दफ्तर बना होता है। इस तरह भगवान का एक छोटा सा केंद्र बनाने के बाद में बाकी सारी इमारत, सारा स्थान लोक मंगल के लिए होता है। पहले भारतवर्ष में भी ऐसा ही किया जाता था और किया भी जाना चाहिए, लेकिन आज तो मंदिरों की दशा देख कर हंसी आती है और क्रोध भी। आज मंदिरों का सारा-का सारा धन चंद लोगों के निहित स्वार्थ के लिए खरच हो जाता है। जो कुछ भी चढ़ावा या दान आया, कुछ निहित स्वार्थ के लिए मठाधीशों और मंदिरों के स्वामी और दूसरे महंतों के पेट में चला गया। मित्रो! वह अनावश्यक धन, हराम का धन जब उन लोगों के पास आया तो उन्होंने क्या-क्या किया? आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। पंडा-पुजारियों, महंतों और मठाधीशों की हकीकत मुझे मालूम है। आप तो केवल उनकी बाहर की शकल जानते हैं। मुझे उनके पास रहने का मौका मिला है। मैं जानता हूं कि समाज के कई किस्म के तबके अगर हैं, तो उनमें से एक तबका इन लोगों का भी है, जो धर्म का कलेवर या धर्म का दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। इनके स्वार्थों को पूरा करने के लिए आज का धर्मतंत्र है-मंदिर। तो क्या मंदिर सिर्फ इसी काम के लिए है? क्या इन परिस्थितियों को बदला नहीं जाना चाहिए? अगर हमको ख्याल है कि जनता का इतना धन ठीक तरीके से उपयोग किया जाए तो आज के जो मंदिर हैं, उनकी व्यवस्था पर नये ढंग से विचार करना पड़ेगा। जिन लोगों के हाथ में उनका नियंत्रण है, उनको समझाना पड़ेगा और साफ तौर पर कहना पड़ेगा कि लोक मंगल के लिए आप इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ट्रस्टियों को भी समझाया जाना चाहिए। अगर उनकी समझ में यह बात आ जाए कि मंदिर में जितना धन लगा हुआ है, इसमें से थोड़े पैसे से भगवान की पूजा आसानी से की जा सकती है। तो यह तरीका है, जिस पर हमें गौर करना ही होगा।

रीडर्स मेल

पर्यटन में साफ-सफाई जरूरी

इस समय स्कूल-कॉलेज में छुट्टियों का दौर शुरू हो गया है। यहां तक कि जिला अदालत, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भी छुट्टियों का कैलेंडर जारी होता है। अधिकतर पर्यटक भारत के विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जाते हैं। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के पश्चात पर्यटकों को राष्ट्रविरोधी तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर जाना चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों और उनके जिलों, नगरों में अन्य राज्यों से पर्यटक गर्मी के महीनों में लाखों-करोड़ों की संख्या में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन इन स्थानों पर पीने के पानी की बोतल तथा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक तथा इस तरह के अन्य प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले विभिन्न पदार्थों को छोड़ देते हैं। साफ-सफाई पर किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए जरूरी है कि इन राज्यों में गर्मी के महीनों में घूमने जाने वाले पर्यटकों को विशेष रूप से साफ-सफाई पर ध्यान देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की गंदगी तथा खाद्य पदार्थ को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ादान का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर तो देखा गया है कि धीरे-धीरे अब ये शहर और राज्य भी पर्यटकों के कारण प्रदूषित होते जा रहे हैं।

मीना धानिया, ई मेल से

जनाकांक्षा पूरी करने की उम्मीद

देश की राजधानी में रेखा गुप्ता सरकार ने 100 दिनों की अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। इस अवसर पर भाजपा ने रेखा गुप्ता सरकार की सराहना की है जबकि विपक्ष ने सरकार की खामियों को जनता के समक्ष रखा है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो रेखा गुप्ता सरकार द्वारा आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करना बड़ी उपलब्धि है जिसके माध्यम से बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अच्छी देखभाल हो सकेगी। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने 'देवी' नाम से ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया है। यह ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी शुरुआत है। सरकार का तीसरा कदम दिल्ली के नालों की गहराई से सफाई करना है। हालांकि नालों से निकली गंदगी का ढेर अभी भी सड़कों पर पड़ा हुआ है जिस पर सरकार को अविलंब ध्यान देना जरूरी है। प्रदूषित यमुना पर दिल्ली सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। हालांकि अभी सफलता नहीं मिली है। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं को जरूर पूरा करेगी

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

जश्न बना जनसंहार

बैंगलुरु की धरती पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु की प्रथम जीत का स्वप्निल उल्लास उस क्षण भयावह दुःस्वप्न बन गया जब जनसागर की अराजकता, प्रशासन की चूक और जन-उन्माद की अनियंत्रित ऊर्जा ने ग्यारह जिंदगियों को स्थायी मौन में बदल दिया और पचास से अधिक शरीरों को कराहने पर छोड़ दिया। आयोजकों को प्रचार का लोभ था, वहीं जनता को व्यवस्था का भरोसा न था; भीड़ की सुरक्षा की उपेक्षा ने जश्न को जन-संहार में बदल डाला। मैदान में न अनुशासन था, न आपातकालीन निकासी की चेतना-और यही बना विनाश का कारण। जागरूकता को प्राथमिकता दी जाए तो भारत उत्सवों की भूमि के साथ-साथ उत्तरदायी नागरिकता का आदर्श भी बन सकता है। यह चेतावनी है कि उत्सव तभी सार्थक है, जब उसमें जीवन सुरक्षित हो।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

बेंगलुरू त्रासदी...

बैंगलुरू त्रासदी से महत्वपूर्ण सबक लिए जाने चाहिए। मृतकों के परिवार जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, इसलिए तत्काल कठोर सुरक्षा प्रोटोकाल बनाने की आवश्यकता है। 4 जून को बैंगलुरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में त्रासद भगदड़ के कारण पूरा शहर आघात से दुःखी है। 18 साल में रायल चैलेंजर्स बैंगुलरू-आरसीबी की पहली विजय के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल समारोह विनाशकारी विभीषिका में बदल गया जिसमें 11 निरपराध प्रशंसकों की मौत हो गई तथा बहुत से घायल हो गए। इस आयोजन में स्टेडियम में 2.5 लाख लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई जिसकी अधिकतम क्षमता केवल 33,000 थी। इससे यह आयोजन घातक भगदड़ में बदल गया जिसका कारण खराब प्रबंधन, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा तथा समन्वय की कमी थी। स्टेडियम में गेट नंबर 3 के बाहर भगदड़ मची जहां भारी भीड़ के दबाव से गेट टूट गया। यह केवल प्रशंसकों की अति-उत्साही भीड़ के कारण नहीं, बल्कि ढांचागत कमी तथा प्रशासनिक विफलता के कारण था जिसके लिए क्रिकेट संगठन और राज्य प्रशासन की विफलता जिम्मेदार है। प्राथमिक जांच से पता चलता है कि यह त्रासदी कानून-व्यवस्था भंग होने तथा संवाद एवं जिम्मेदारी में कमी के कारण थी। आरसीबी ने 4 जून को सवेरे सोशल मीडिया के माध्यम से एक विजय परेड की घोषणा की थी, जबकि इसके लिए कर्नाटक पुलिस कानून के अंतर्गत अनिवार्य अनुमति भी नहीं प्राप्त की गई थी। इसके पहले रात में उसके द्वारा परेड की प्रार्थना को पुलिस ने खारिज कर दिया था क्योंकि इसमें भारी भीड़ आने का खतरा था। लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट संगठन ने यह घोषणा कर दी और सवेरे 9 बजे तक विभिन्न प्लेटफार्मों पर यह घोषणा वाइरल हो गई थी जिससे दसियों हजार प्रशंसक सड़कों पर आ गए थे। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने विधान सौध में आरसीबी टीम के अभिनन्दन की अपनी योजना घोषित की। स्टेडियम से केवल एक किलोमीटर दूर यह आयोजन भी लगभग उसी समय होना था। इसके परिणामस्वरूप बैंगलुरू पुलिस पर बहुत दबाव पड़ा जो उसकी क्षमता से बाहर था।

आईपीएल फाइनल के कारण अधिकारी पहले ही देर रात ड्यूटी से लौटे थे और अब उनसे टीम के हवाईअड्डे पर पहुचने पर सुरक्षा, विधान सौध तक परिवहन तथा स्टेडियम के आयोजन की सुरक्षा की उम्मीद की जा रही थी। यह काम बहुत जल्दी और सीमित क्षमता के बावजूद किया जाना था। लापरवाही के लिए आरसीबी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसियेशन-केएससीए और एक निजी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी 'डीएनए' के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक सरकार ने मामले की पूरी जांच के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने भी त्रासदी का स्वतः संज्ञान लेकर सभी संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन राजनेता भी इस त्रासदी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। टीम के स्वागत की पहल करने वाले उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सरकारी और स्टेडियम आयोजनों में भाग लिया था। इस त्रासदी को एक चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। इससे बिना समुचित सुरक्षा जांचों, समन्वय और भीड़ प्रबंधन के आयोजन करने के खतरे स्पष्ट होते हैं। 4 जून को जो कुछ हुआ वह एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इस विभीषिका को रोका जा सकता था जिसका कारण प्रशासनिक अर्थव्यवस्था तथा परस्पर विरोधी आकांक्षायें थीं। कोई भी सार्वजनिक आयोजन बिना अच्छे नियोजन, समुचित संप्रेषण तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से मानव जीवन का सम्मान किए बिना नहीं होना चाहिए। क्रिकेट टीम की विजय एकजुटता, प्रगति और प्रेरणा का माध्यम बननी चाहिए और इसे 'शोक दिवस' में नहीं बदलना चाहिए। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है तथा मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक सलाहकार को भी हटा दिया है, पर सरकार और आयोजकों से जनता की नाराजी इसके बावजूद बनी हुई है। इस त्रासदी से राज्य सरकार की छवि को गहरा धक्का लगा है। आशा है कि बैंगलुरू की त्रासदी से समुचित सबक सीखा जाएगा तथा इसके लिए पुलिस व प्रशासन के स्तर पर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी ताकि फिर ऐसी दुःखद घटना न हो।

ऑपरेशन सिंदूरः सटीक हमले से दहला पाक

तकनीकी शक्ति व रणनीतिक स्पष्टता का परिचय देते हुए भारत के आपरेशन सिंदूर ने आधुनिक युद्ध के मानक तय किए और पाकिस्तान को 80 घंटे के भीतर युद्धविराम की प्रार्थना को मजबूर कर दिया।

विनायक भट
(लेखक, सेवानिवृत्त कर्नल हैं)

भारत के निर्णायक आपरेशन सिंदूर के 80 घंटे के भीतर पाकिस्तान द्वारा अचानक युद्धविराम की प्रार्थना से अनेक विश्लेषक और रणनीतिज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। पाकिस्तान ने अचानक अपने सैनिक आपरेशन 'बुनयान मरसूस', अर्थात 'शीशे की दीवाल' को वापस लेने की घोषणा कर लंबे युद्ध के बजाय सफेद झंडा लहरा दिया। ऐसे में सवाल है कि इस त्वरित यूटर्न का कारण क्या था? इसका जवाब भारतीय वायुसेना के सटीक निशाने थे जिन्होंने पाकिस्तान के सर्वाधिक सुरक्षित सैनिक ठिकानों को नष्ट कर दिया। इनमें खासकर सीमा से बहुत दूर स्थित हवाईअड्डों के कमांड और कंट्रोल सेंटर शामिल थे। इन सर्जिकल स्ट्राइकों से पाकिस्तान की आपरेशन क्षमता को भारी धक्का लगा और युद्ध जारी रखने की उसकी इच्छाशक्ति समाप्त हो गई। आपरेशन सिंदूर का कारण पहलगाम में हुआ भयानक आतंकी हमला था जो 2019 में पुलवामा धमाकों के बाद सबसे घातक था। इस हमले की जिम्मेदारी 'द रेजिस्टेंस फ्रंट'-टीआरएफ ने ली थी जो आतंकी संगठन लश्करे तैयबा-एलईटी से सीधे जुड़ा है। लश्करे तैयबा को पाकिस्तानी अवस्थापना का परोक्ष समर्थन प्राप्त है। विश्व स्तर पर व्यापक निन्दा के बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके सेना प्रमुख पूरी बेशर्मी के साथ राज्य-प्रायोजित आतंकवाद पर खामोश हैं। भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेज और सुनियोजित थी। 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर बहुत दूर तक आतंकी ढांचों पर सर्जिकल सटीकता से हमला करने की अपनी क्षमता में व्यापक सुधार किया है जिसे अत्यधिक सटीक खुफिया सूचनाओं से सहायता मिलती है। इस बार 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना लगाया गया जिनमें बहावलपुर में जैशे मुहम्मद-जेईएम का प्रशिक्षण शिविर तथा मुरिदके में लश्करे तैयबा-एलईटी का मुख्यालय शामिल हैं।

हालांकि, पाकिस्तानी जवाबी हमला भी व्यापक था, पर यह निष्प्रभावी रहा। ड्रोन हमले, सीमावर्ती गांवों पर गोलाबारी तथा पाकिस्तानी वायुसुना द्वारा लक्षित भारतीय सैनिक ठिकानों पर निशाना लगाने के विफल प्रयास इनमें शामिल हैं। इसके जवाब में भारत ने भी सटीक हमला करते हुए पाकिस्तानी के वायुरक्षा राडारों, सतह से हवा में मार करने वाली सैम मिसाइल साइटों, समन्वित हवाई रक्षा व्यवस्थाओं-आईएडीएस तथा 13 स्थानों पर पाकिस्तानी वायुसेना-पीएएफ के ठिकानों पर निशाना लगाया। ये हमले न केवल टैक्टिल, बल्कि क्षमता प्रदर्शित करने वाले थे जिनका उद्देश्य भारत की तकनीकी बढ़त दिखाना तथा जवाब देने या युद्ध का विस्तार करने की पाकिस्तानी क्षमता को ध्वस्त करना था। इन हमलों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम पाकिस्तान के बहुत गहराई में छिपे मजबूत ठिकानों-एचडीबीटी का विनाश करना था। इन भूमिगत ठिकानों का निर्माण हवाई और नाभिकीय हमलों से बचने के लिए किया गया था।

दुनिया भर की सेनायें अपने महत्वपूर्ण कमांड, कंट्रोल, कम्युनीकेशन व इंटेलीजेंस केन्द्रों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्थायें करती हैं। पाकिस्तान के नेटवर्क में कम से कम ऐसे 22 भूमिगत बंकर-एचडीबीटी शामिल थे जो उसके प्रमुख हवाई ठिकानों तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों जैसे इस्लामाबाद और कराची के निकट थे। इन सुविधाओं को कई पर्तों वाली कंक्रीट की दीवालों तथा स्टील रेबार से मजबूत किया गया था तथा इनमें उत्कृष्ट गर्मी पैदा करने, वेंटीलेशन और एयरकंडीशनिंग व्यवस्थायें लगाई गई थीं ताकि लंबे समय तक भूमिगत रहा जा सके। आपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक दो महत्वपूर्ण एचडीबीटी नष्ट कर दिए जिनमें से एक चकलाला हवाईअड्डे के निकट इस्लामाबाद में था दूसरा पोटोहर पठार पर मुरिद हवाईअड्डे के निकट था। भारतीय सैनिक कार्रवाई महानिदेशक-डीजीएमओ एयरमार्शल ए.के. भारती ये कमांड तथा कंट्रोल एयर डिफेंस सेंटर थे। लेकिन इस लेखक के अनुसार वे व्यापक रूप से राडार डेटा, इंटेलीजेंस जानकारियों तथा हवाई कार्रवाइयों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले सी41 केन्द्र थे।

चकलाला हवाईअड्डे पर हमला तकनीकी रूप से मास्टरस्ट्रोक था। चकलाला पर भूमिगत सुविधा का निर्माण 1990 के दशक में जनरल एलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किया गया था जो भूमिगत सैनिक ढांचागत संरचना बनाने में माहिर है। यह लगभग 750 वर्ग मीटर में फैला था और इसे पाकिस्तान का सर्वाधिक उत्कृष्ट वायुरक्षा केन्द्र माना जाता था। वास्तव में वीआईपी व विदेशी सैनिक प्रतिनिधिमंडल अक्सर इस बंकर को देखने आते थे और पाकिस्तानी स्वदेशी तकनीकी समन्वय की प्रशंसा करते थे। चकलाला पर भारतीय वायुसेना का निशाना अत्यधिक सटीक हमले का प्रदर्शन था। सेटेलाइट से मिली तस्वीर से स्पष्ट है कि बम ने बहुत छोटे एचवीएसी शैफ्ट से प्रवेश किया जो मुश्किल से 45 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसका अर्थ है कि इसमें गलती की कोई संभावना नहीं थी और इसके लिए सटीक खुफिया सूचना, उचित कोआरडीनेट्स तथा सर्वोत्तम पाइलेटों व उपलब्ध हथियारों की तैनाती आवश्यक थी। इस बम का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने कंक्रीट की छत का एक बड़ा हिस्सा हवा में उड़ा दिया तथा पूरी भूमिगत सुविधा एवं भीतर मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान को मलबा साफ करने में कई दिन लगे और आखिरकार उसने वहां मृतक कर्मियों को दफन रहने देने का निर्णय किया क्योंकि वहां और कुछ बचा ही नहीं था। यह हमला संभवतः हवाई युद्ध के इतिहास में अपने किस्म का पहला हमला था जिसने इतने छोटे तथा बहुत गहराई में स्थापित ठिकाने पर पूरी सटीकता से प्रहार कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। मुरिद हवाईअड्डे की भूमिगत सुविधा और ज्यादा संवेदनशील थी। पाकिस्तान के स्पेशन वर्क्स डिपार्टमेंट ने पहले के निर्माणों से सबक लेते हुए एचवीएसी के शैफ्टों को दूर बनाया था ताकि वेंटीलेशन डक्टों द्वारा सटीक हमले से बचा जा सके। इस चुनौती का सामना करते हुए भारतीय वायुसेना ने बंकर के केन्द्रीय हिस्से पर सीधे निशाना लगाना तय किया। सेटेलाइट तस्वीरों से स्पष्ट है कि एक छोटे से छेद से बम ने भीतर प्रवेश किया और वह सतह के बजाय भीतर जाकर फटा। पाकिस्तान ने फौरन इस छेद को सीमेंट से बंद कर दिया ताकि वह सेटेलाइटों से प्रमाण छिपा सके।

इस प्रकार भारत ने सटीक खुफिया जानकारियों तथा सटीक हथियारों के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा अपने महत्वपूर्ण कमांड सेंटरों को जमीन के भीतर छिपाने का प्रयास विफल कर दिया। सरगोधा और जकोकाबाद में अन्य हवाईअड्डों के विनाश के साथ ही इन दो एचडीबीटी के विनाश ने पाकिस्तान की वायु रक्षा कमांड और एयर आपरेशन्स ढांचे को कई महीनों के लिए विकलांग बना दिया है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने दो बंकरों को नष्ट किया जिनमें से एक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट संभवतः पीएएफ चीफ आफ एयर स्टाफ के लिए था। अभी हाल ही में मार्च, 2025 में इन बंकरों को और मजबूत किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इनको बरबाद कर दिया गया। इस प्रकार पाकिस्तान की हवाई क्षमता विखंडित और निष्प्रभावी हो गई। इसके कारण सीएएस के आदेश फील्ड कमांडरों या विमानों तक नहीं पहुंच सकते थे। इससे हवाई युद्ध छेड़ने या नाभिकीय विकल्प आजमाने की पाकिस्तान की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। भारतीय वायुसेना के सटीक हमलों का लक्ष्य पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय धमकी को मूर्त रूप देने से रोकना तथा इसके साथ ही पाकिस्तान के सैनिक ढांचे पर विनाशकारी प्रहार करना था। यह विनाश इतना भयंकर था कि नाभिकीय विकल्प छोड़ कर पाकिस्तान की छवि मिट्टी में मिल गई। इस विनाश तथा और अपमान झेलने से बचने के लिए उसने मजबूरी में जल्दी युद्धविराम की प्रार्थना की। इसके साथ ही भारत ने कठोर राजनयिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सिंधु जल संधि स्थगित कर दी तथा आतंकवाद को समर्थन बंद करने तक पाकिस्ता का पानी बंद कर दिया। इस प्रकार हवाई हमलों से लेकर आर्थिक हमले तक बहुआयामी दबाव राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक नया और समन्वित दृष्टिकोण बन गया है। केवल 80 घंटे में भारतीय सेना ने वह उपलब्धि प्राप्त की जिसे असंभव माना जाता था।

ईश्वर की तलाश की कोई उम्र नहीं

“ईश्वर की खोज कोई भविष्य का कार्य नहीं है। यह एक वर्तमान आमंत्रण है।”

साक्षी सेठी
(लेखक एक काउंसलर और शिक्षक हैं)

आज की दुनिया में, जीवन कभी न खत्म होने वाली दौड़ है - अलार्म, डेडलाइन, ईमेल, मीटिंग, लक्ष्य और लगातार बढ़ती टू-डू लिस्ट। हम लगातार गति में रहते हैं, सफलता, पहचान और आराम की तलाश में। लेकिन इस सारी कोशिशों में, एक जरूरी सच्चाई अक्सर खो जाती है- बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है - सिवाय ईश्वर की आपकी खोज के। इसके बारे में सोचें। ज्यादातर लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू या डॉक्टर के पास जाने से चूकने का सपना भी नहीं देखते। फिर भी, ईश्वर के साथ समय? वह अक्सर टल जाता है, स्थगित हो जाता है या पूरी तरह से भूल जाता है। आध्यात्मिकता हमारी सूची में सबसे नीचे खिसक जाती है, जरूरी लेकिन अक्सर महत्वहीन चीजों के कारण किनारे हो जाती है। हम खुद से कहते हैं कि बाद में समय होगा - प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, बच्चों के बड़े होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जिंदगी कभी भी धीमी नहीं पड़ती। हमेशा एक और तूफान, एक और मील का पत्थर, एक और विकर्षण होता है। समय एक खामोश चोर है। कोई भी अगले पल की गारंटी नहीं दे सकता। और सारी अव्यवस्था के नीचे, आत्मा चुपचाप पुकार रही है - हमारे अस्तित्व की गहराई से फुसफुसाते हुए, हमें याद दिलाते हुए कि हम अपनी दिनचर्या, अपनी उपलब्धियों या अपने सोशल मीडिया व्यक्तित्व से कहीं बढ़कर हैं।

हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, जो जुड़ाव, शांति और अर्थ की चाहत रखते हैं। हम खुद को इस तरह के विचारों से शांत करते हैं, मैं बाद में भगवान पर ध्यान केंद्रित करूंगा। लेकिन बाद में अनिश्चित है। ईश्वर की खोज कोई भविष्य का कार्य नहीं है - यह एक वर्तमान आमंत्रण है। कल्पना कीजिए कि आप घने जंगल में खो गए हैं। क्या आप रास्ता खोजने से पहले रात होने का इंतजार करेंगे, या आप अभी भी रोशनी होने पर शुरू करेंगे? जवाब स्पष्ट है।

> ईश्वर की खोज आकाश में किसी आकृति को खोजने या मंदिर या वेदी खोजने के बारे में नहीं है। यह आंतरिक परिवर्तन के बारे में है - अधिक दयालु, अधिक धैर्यवान, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक जागृत बनना। जैसे-जैसे हम ईश्वर की खोज करते हैं, हम हर जगह पवित्रता को देखना शुरू करते हैं - अजनबियों में, दुख में, प्रकृति में और यहाँ तक कि खुद में भी।

यह आंतरिक यात्रा पूर्णता, अनुष्ठान या धार्मिक प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह उपस्थिति के बारे में है। ईश्वर हमसे दोषरहित होने के लिए नहीं कह रहा है। वह बस हमसे प्रकट होने के लिए कह रहा है - अपनी लालसा, अपनी ईमानदारी, अपनी टूटन, अपनी आशा के साथ। ईश्वर की ओर एक भी, ईमानदार कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसा कि भगवद गीता हमें आश्वस्त करती है, सही दिशा में किया गया थोड़ा सा प्रयास भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम गलती से मानते हैं कि हम समय को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अप्रत्याशित नुकसान, बीमारियाँ या वैश्विक संकट जल्दी ही उस भ्रम को तोड़ देते हैं।

एक ऐसी दुनिया में जो लगातार कमज़ोर होती जा रही है, ईश्वर की खोज न केवल महत्वपूर्ण है - यह अत्यावश्यक है। परंपराओं और सदियों से, रूमी, रामकृष्ण, जीसस और बुद्ध जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने एक सुसंगत संदेश साझा किया है- अभी खोजो। कुछ हासिल करने के बाद नहीं। जीवन के स्थिर हो जाने के बाद नहीं। तूफान के गुजर जाने के बाद नहीं। अभी खोजो। अभी क्यों? क्योंकि आत्मा तालियों, धन या छुट्टियों से तृप्त नहीं होती।

अहंकार प्रशंसा से तृप्त होता है; आत्मा मौन, समर्पण और पवित्रता से तृप्त होती है। वास्तविक शांति अधिक प्राप्त करने से नहीं बल्कि गहराई में जाने से आएगी - शांति में, प्रेम में, ईश्वर में। और ईश्वर की खोज आकाश में किसी आकृति को खोजने या मंदिर या वेदी खोजने के बारे में नहीं है। यह आंतरिक परिवर्तन के बारे में है - अधिक दयालु, अधिक धैर्यवान, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक जागृत बनना। जैसे-जैसे हम ईश्वर की खोज करते हैं, हम हर जगह पवित्रता को देखना शुरू करते हैं - अजनबियों में, दुख में, प्रकृति में और यहाँ तक कि खुद में भी।

यह बदलाव हमें अहंकार से जीने से सार से जीने की ओर ले जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर दूर नहीं है। हम पहाड़ों या महासागरों से अलग नहीं हैं। जैसा कि पवित्र कुरान कहता है, हम आपकी गले की नस से भी ज्यादा करीब हैं। ईश्वर पहले से ही निकट है। यह हम ही हैं जो बह गए हैं। आध्यात्मिक यात्रा बस एक वापसी है - हमारे उस हिस्से की ओर जो पहले से ही प्रेम को जानता है, पहले से ही शांति को जानता है, पहले से ही सत्य को जानता है।

तो, रुकें। सांस लें। अपनी आँखें बंद करें। प्रार्थना करें, भजन गुनगुनाएँ, मोमबत्ती जलाएँ, या चुपचाप टहलें। जो भी आपको अंदर की ओर खींचता है, वह करें। शांति के उस पल को आपको याद दिलाएँ कि आपकी आत्मा स्रोत से अलग नहीं है। क्योंकि अंत में, बाकी सब कुछ - करियर, उपलब्धियाँ, संपत्ति - बीत जाएगा। जो बचता है वह है ईश्वर के लिए आत्मा की शाश्वत लालसा। यही एक ऐसा रिश्ता है जो कभी फीका नहीं पड़ेगा, एक ऐसा प्रयास जो बाकी सभी को अर्थ देता है। इसलिए इंतज़ार न करें। सही समय कल नहीं है - यह अभी, यहीं, अभी का क्षण है।

आप की बात

दिल्ली की उपलब्धियां

देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नीत सरकार द्वारा 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाई गई है। इस अवसर पर भाजपा ने रेखा गुप्ता सरकार की सराहना की है जबकि विपक्ष ने सरकार की खामियों को जनता के समक्ष रखा है। यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो रेखा गुप्ता सरकार द्वारा आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करना एक बड़ी उपलब्धि है जिसके माध्यम से देश के लोगों व खासकर 70 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल हो सकेगी। इसी प्रकार दिल्ली सरकार ने देवी नामक योजना से ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया है जो ग्रामीण इलाकों के लिए एक अच्छी शुरुआत है। सरकार का तीसरा कदम दिल्ली के नालों-नालियों की गहराई से सफाई करना है। हालांकि नालों से निकली गंदगी का ढेर अभी सड़कों पर पड़ा हुआ है जिस पर सरकार को अविलंब ध्यान देना जरूरी है। प्रदूषित यमुना को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार ने गंभीर प्रयास किया है हालांकि अभी इस प्रयास में सफलता मिलने में कुछ समय लगेगा। उम्मीद है कि दिल्ली में अब तीन इंजनों वाली सरकार इसे सचमुच देश की राजधानी के रूप में गौरवान्वित करने के साथ ही दुनिया में भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में प्रयास करेंगी।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

अव्यवस्था का परिणाम

बैंगलुरु की धरती पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्रथम जीत का स्वप्निल उल्लास उस क्षण भयावह दुःस्वप्न बन गया जब जनसागर की अराजकता, प्रशासन की चूक और जन-उन्माद की अनियंत्रित ऊर्जा ने ग्यारह जिंदगियों को स्थायी मौन में बदल दिया और पचास से अधिक शरीरों को कराहते छोड़ दिया। जहाँ आयोजकों को था केवल प्रचार का लोभ, वहीं जनता को न था व्यवस्था का भरोसा। भीड़ की आकांक्षा और सुरक्षा की उपेक्षा ने मिलकर ऐसा कुचक्र रचा जिसने जश्न को जन-संहार में बदल डाला। सुरक्षा प्रबंधन के नाम पर जब योजनाएँ केवल कागज़ पर थीं और मार्गदर्शन केवल नारों में सीमित तब मैदान में न अनुशासन था न आपातकालीन निकासी की चेतना और यही बना जनविनाश का कारण। सरकारी घोषणाओं में सहायता राशियाँ आईं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, परंतु उन मासूम मृतकों की चीख, उन घायल बच्चों की सिसकी और उन परिजनों की खामोश पीड़ा को कोई मौद्रिक उपाय न शांति दे सका। यदि भारत को जन-उत्सवों की भूमि बने रहना है तो उसे जन-संवेदनशीलता और जन-सुरक्षा की वैज्ञानिक संस्कृति अपनानी होगी जिसमें प्रशिक्षित स्वयंसेवक, मार्गदर्शक संकेत तथा बहिर्गमन के स्पष्ट उपाय हों।

- अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

बच्चों का स्वास्थ्य

वर्तमान दौर में अच्छी सेहत के लिए संतुलित खान पान होना बेहद जरूरी है। हम किस तरह का भोजन कर रहे, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा, यह चिंतन मनन जरूरी होता है। विशेषकर बच्चों की सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान देना माता-पिता और परिजनों की कर्तव्य निष्ठा में शामिल होना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट चिंता की लकीरें बढ़ाती नजर आती है! मेक अमेरिका हेल्दी अगेन शीर्षक सरकारी रिपोर्ट में मौजूदा पीढ़ी को अब तक की सबसे बीमार पीढ़ी बताया है! 7.3 करोड़ बच्चों में से 40 प्रतिशत से अधिक किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है! बच्चों की सेहत पर संकट मंडरा रहा है। खराब खान-पान शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है! मोटापा, खराब मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक अक्षमता के कारण 75 प्रतिशत युवा सैन्य सेवा के अयोग्य है। रिपोर्ट के अनुसार जंक फूड, केमिकल और गैर-जरुरी दवाएं बीमारियों की वजह बन रही है। बच्चों का स्वास्थ्य भारत में भी अच्छा नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं जिससे उनमें डायबिटीज बढ़ने की आशंका है। बच्चों के स्वास्थ्य को सभी लोगों की ओर से प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

- योगेश जोशी, बड़वाह

ट्रंप-मस्क अलगाव

डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर थी। एक तरफ दुनिया के सबसे प्रभावशाली राजनेता और दूसरी तरफ सबसे अमीर उद्योगपति। लेकिन अब इन दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे हैं जो जुबानी जंग का रूप ले चुके हैं। हाल ही में ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनियों - टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ सरकारी अनुबंधों में कटौती की घोषणा की। इसके जवाब में एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि वह ड्रैगन कैप्सूल की सेवा बंद कर सकते हैं। यह कैप्सूल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य सामग्री को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिकी सरकार की बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर यान विफल हो गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मस्क की यह तकनीक नासा के अंतरिक्ष अभियानों की रीढ़ बन चुकी है। इसके अलावा नासा ने कई सैन्य अभियानों में भी स्पेसएक्स की मदद ली है। मस्क ने एक पार्टी बनाने का इरादा जता कर ट्रंप से अलगाव और बढ़ा दिया है। यह अमेरिकी राजनीति की महत्वपूर्ण परिघटना है।

- दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 96

आरबीआई का साहसिक प्रयास

दुनिया में बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले सप्ताह भारतीय वित्तीय प्रणाली और व्यापक अर्थव्यवस्था को कुछ निश्चितता प्रदान करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चालू वित्त वर्ष में अपनी दूसरी बैठक के बाद शुक्रवार को रीपो दर 50 आधार अंक घटाकर 5.5 फीसदी कर दी। बाजार को रीपो दर में 25 आधार अंक की कमी का अनुमान था।

इतनी बड़ी कटौती का मकसद निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियों की गति बढ़ाना है। इस तरह, नीतिगत दरों में कमी के मौजूदा चक्र में एमपीसी रीपो दर में 100 आधार अंक की कमी कर चुका है। आरबीआई ने नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) भी 100 आधार अंक घटाकर इसे 3 फीसदी करने का निर्णय लिया। सीआरआर में यह कमी चार चरणों में पूरी की जाएगी। आरबीआई के इस कदम से वित्तीय प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी आएगी। इससे नीतिगत दर में कटौती का लाभ जल्द मिलेगा और बैंकिंग प्रणाली के लिए पूंजी जुटाने पर लागत भी कम हो जाएगी।

वित्तीय प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने हाल के महीनों में कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक इस वर्ष की शुरुआत से अब तक वित्तीय प्रणाली में 9.5 लाख करोड़ रुपये नकदी डाल चुका है। इसके परिणामस्वरूप भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) नकदी समायोजन व्यवस्था के निचले सिरे के करीब पहुंच गई है। डब्ल्यूएसीआर मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है। इसका यह भी आशय है कि नीतिगत दरों में कटौती से जो अनुमान थे, वास्तविक नीति समायोजन उससे अधिक रहा है। रीपो दर में कटौती का लाभ पहुंचाने के लिए आरबीआई डब्ल्यूएसीआर संभवतः नकदी समायोजन व्यवस्था के निचले सिरे पर रखेगा।

उल्लेखनीय है कि एमपीसी ने न केवल रीपो दर में अनुमान से अधिक कमी की है बल्कि बाजार को यह संदेश भी दिया है कि 'मौजूदा परिस्थितियों में आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए आरबीआई के पास काफी कम गुंजाइश मौजूद है'। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को मदद पहुंचाने के अपनी तरफ से लगभग सभी प्रयास कर लिए हैं। आरबीआई ने अपना नीतिगत रुख भी 'उदार' की जगह अब 'तटस्थ' कर लिया है जो यह संकेत दे रहा है कि एमपीसी की अगली बैठक में दरें नहीं भी घटाई जा सकती हैं।

बाजार एवं निवेशकों के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या एमपीसी मौजूदा चक्र में रीपो दर उस स्तर तक पहुंचा चुकी है जहां इसमें और कमी की गुंजाइश नहीं है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समग्र मुद्रास्फीति दर में कमी के बाद रीपो दर में बड़ी कटौती की गुंजाइश बनी थी। अप्रैल में समग्र मुद्रास्फीति दर कम हो कर 3.2 फीसदी रह गई। एमपीसी ने इस साल के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 फीसदी से घटाकर 3.7 फीसदी कर दिया। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वास्तविक मुद्रास्फीति एमपीसी के अनुमान से भी कम रहेगी।

एमपीसी के अनुमान सही साबित हुए तो इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में औसत मुद्रास्फीति 4 फीसदी से थोड़ी अधिक रह सकती है। आरबीआई के अर्थशास्त्रियों ने पहले यह बताया है कि तटस्थ दर 1.4 फीसदी से 1.9 फीसदी के बीच रहती है। यह मानते हुए कि एमपीसी इस अनुमान के साथ आगे बढ़ती है और मौद्रिक नीति दूरदर्शी रखने की जरूरत है तो आगे दरें और घटने की संभावना कम रहेगी। अगर मुद्रास्फीति और निचले स्तर पर आई तो दरों में अतिरिक्त कमी की गुंजाइश बढ़ जाएगी मगर यह आगामी महीनों में तो नहीं होगी। एमपीसी ने आर्थिक वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है मगर यह स्पष्ट नहीं है कि दरों में कटौती से आर्थिक वृद्धि में किस सीमा तक उछाल आने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष भी वृद्धि दर समान स्तर पर रही थी जिसे देखते हुए मध्यम अवधि की संभावित वृद्धि दर 7 फीसदी से ऊपर पहुंचाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप का दायरा मौद्रिक उपायों तक सीमित न रखकर इसे आगे बढ़ाना होगा।

दो मुश्किल मोर्चे और शतरंज की चाल

चीन के लिए पाकिस्तान केवल भारत को दबाने और फंसाने का सस्ता हथियार रहा है। मगर अब वह पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी थिएटर कमान का ही हिस्सा मानने लगा है।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

इतिहास हर जंग को एक नाम देता है। सरकार के हिसाब से लड़ाई बीच में रुकी जरूर थी मगर कुल मिलाकर 87 घंटे तक चलती रही। तो क्या आने वाली पीढ़ियां इसे केवल 87 घंटे की जंग कहेंगी?

किंतु मेरी राय में इसे एक नाम तो दिया ही जाए, जिसका हैशटैग चलाया जा सके। हमने अभी-अभी जो देखा, वह दो मोर्चे वाली जंग में पहली चाल है। आप इसे झांकी कह सकते हैं। दिमाग, हौसले और फौजी ताकत की लंबी जंग में ये शुरुआती चालें हैं। इसे और अच्छी तरह से कैसे समझाया जाए?

इसे समझाने के लिए क्रिकेट का कोई उदाहरण उठाकर यहां डालने से मैं एकदम परहेज करूंगा। उसके बजाय मैं शतरंज पर जाऊंगा। चूंकि इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने पहलगाम से की थी और चीन के हथियारों, तकनीक तथा इशारों पर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए मान लेते हैं कि सफेद मोहरे उनके हाथ में हैं। चूंकि सफेद मोहरों वाला ही पहली चाल चलता है, इसलिए यह अतीत की जानी पहचानी पीके4 चाल है, जिसे अब ई4 कहा जाता है।

इस चाल में प्यादे को दो खाने आगे राजा के सामने बढ़ाया जाता है ताकि सामने वाला खिलाडी अपनी चाल चले। इसके बाद खिलाड़ी इटालियन गेम पर जा सकता है, स्कॉच गेम पर जा सकता है या रुई लोपेज चल सकता है। मुझे किंग्स गैंबिट ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें तेवर आक्रामक होते हैं, कई तरह की चाल चली जा सकती हैं। पाकिस्तान और चीन इसे साथ मिलकर खेल रहे हैं और उन्होंने प्यादा आगे बढ़ा भी दिया है। पाकिस्तान सामने है, प्यादा है, जिसे राजा और रानी की यानी चीन की शह मिली है, जिसकी फौज पीछे खड़ी है। वे भारत की चाल का इंतजार कर रहे हैं।

लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। वक्त बीत रहा है। अखबारों में छपी खबरें बताती हैं कि अब सैन्य बल भी 'रेड टीम' बनाने लगी हैं - तेज-तर्रार अफसरों की टीम, जो दुश्मन की तरह सोचती और जवाब देती है। अपनी रेड टीम की तरह सोचिए। इसका अगला कदम क्या होगा?

हमारा कहना है कि हम दो मोर्चों पर जूझते रहे हैं मगर हमने यह कभी नहीं सोचा कि दोनों एक ही वक्त पर सामने आएंगे। 1962 में पाकिस्तानी दूर रहे, बेशक अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव के बीच उन्होंने बदले में कश्मीर पर बातचीत की मांग की। 1965, 1971 और करगिल जंग में चीन दूर ही रहा। लेकिन राजा से दो खाने आगे प्यादा रखने की उनकी चाल बता रही है कि अब तस्वीर बदल गई है।

जंग दो मोर्चों पर चल रही है। बस, चीन को सीधे लड़ाई की जरूरत नहीं लग रही। वे पाकिस्तान की आड़ में छुपे हैं। वे भारत को टक्कर देने के लिए उसे आधुनिक हथियार और उपकरण बेचते रहेंगे, जैसे साल भर के भीतर पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। उनके उपग्रह और दूसरे खुफिया, निगरानी तथा टोही उपकरण भी पाकिस्तान के पास रहेंगे और उसे चीन की सलाह भी मिलेगी। इसीलिए मैंने दो हफ्ते पहले कहा था कि पाकिस्तान अब हमें उकसाने में पांच-छह साल नहीं लगाएगा। अगली हरकत वह जल्दी करेगा।

रेड टीम यही कहेगी कि चीन को भारत से सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को हथियार देते रहने भर से उसका काम हो जाएगा। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खबरें पढ़ी होंगी तो एक खास बात आपने देखी होगी। पूरी लड़ाई में आपने किसी अमेरिकी उपकरण का इस्तेमाल नहीं देखा होगा, एफ-16 विमानों का भी नहीं। स्वीडन के साब एरीये एईडब्ल्यूऐंडसी (हवा में त्वरित चेतावनी तथा नियंत्रण करने वाले) विमान थे, जिनमें चीनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे थे। असल में यह चीन बनाम भारत जंग है, जिसमें पाकिस्तान की फौज को आगे खड़ा कर दिया गया है।

हमें कई दशक से पता है कि चीन हमें बीच में फंसाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अब वह दो कदम आगे बढ़ गया है। पहला कदम था पूर्वी लद्दाख पर पहुंचना और पाकिस्तान के लिए खड़े हमारी फौज के बड़े हिस्से को उलझाना। दूसरा कदम है पाकिस्तान से सीधी सैन्य चुनौती।

सैन्य शतरंज की बिसात पर इस पीके4 या ई4 चाल का भारत ने जिस आक्रामक तरीके से जवाब दिया, उससे दोनों सन्न रह गए। जैसा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे में बताया, उन्हें लगा होग कि 9 और 10 मई की दरम्यानी रात को रॉकेट तथा मिसाइल हमला होने पर भारत घुटने टेक देगा।

मगर भारत ने उसके तमाम ड्रोन और मिसाइल बीच में ही रोक दिए, पाकिस्तान वायु सेना पर धावा बोलकर उसके अड्डे तहस-नहस कर दिए। यह चाल नाकाम होते ही संघर्ष विराम में ही समझदारी थी। रेड टीम अब सोच रही है कि गलती कहां हो गई और अगली चाल के लिए तैयारी कैसे करें।

अब उन्हें चार चिंता हैं - एस-400 की अगुआई में भारत की बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल, खास तौर पर अगर उसे पाकिस्तानी वायुसेना की किसी भी मिसाइल की पहुंच से दूर सुखोई-30 एमकेआई विमान से दागा जाए, चीन के एचक्यू-9 विमान के बावजूद उसकी नाकाफी हवाई रक्षा प्रणाली और ऐंटी-रेडिएशन ड्रोन से इन्हें किसी भी वक्त रोकने तथा खत्म कर देने की भारत की क्षमता।

याद रखिए कि चीन इनसे निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम कर रहा होगा। उनके पास भी एस-400 हैं। वे ब्रह्मोस का जवाब तलाशने के लिए रूस की मदद लेने की कोशिश भी करेंगे। अधिक लंबी दूरी की मिसाइल के साथ एफसी-31 लड़ाकू विमान पहुंच ही रहा होगा। मैं रेड टीम की तरह सोच रहा हूं।

मान लेना चाहिए कि चीन अब पाकिस्तान को भारत के लिए बनाई अपनी वेस्टर्न थिएटर कमान का ही हिस्सा मानता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि चीनी सेना अब पाकिस्तान को अपनी छठी थिएटर कमान मानने लगी है। अगर पाकिस्तान ही भारत को फंसाए रखेगा तो चीन की पश्चिमी थिएटर कमान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं।

पाकिस्तान-चीन संबंधों पर कई किताबें और शोध पत्र लिखे गए हैं। हमें कुछ अहम तारीखों पर नजर दौड़ानी होगी। भारत-चीन सीमा पर स्थिति 1960 में चाऊ एनलाई के दौरे के बाद बिगड़ती है। 28 मार्च 1961 को पाकिस्तान अपनी सीमा तय करने के लिए चीन को चिट्ठी भेजता है, वह सीमा जो कश्मीर के कुछ हिस्से पर उसके गैर-कानूनी कब्जे का नतीजा है।

फरवरी 1962 में भारत के साथ टकराव बढ़ता है और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का पक्ष रखते हुए सर मोहम्मद जफरुल्ला कबूल करते हैं कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में चीन के साथ लगी हुई अपनी सीमा से फौज हटा लेगा। दो महीने बाद 3 मई को दोनों बातचीत करने का संयुक्त बयान जारी करते हैं और भारत विरोध करता रह जाता है। पाकिस्तान और चीन 12 अक्टूबर को सीमांकन के लिए सीधे बातचीत शुरू कर देते हैं। आठ दिन बाद चीनी फौज हमला शुरू कर देती है, जो जंग में तब्दील होता जाता है।

भारत-चीन जंग रुकने के केवल चार महीने बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अचानक पेइचिंग पहुंच जाते हैं और एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत होते हैं। इसमें पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा (शक्सगाम घाटी और आसपास का इलाका) चीन को सौंप दिया जाता है और बदले में पाकिस्तान को हंजा के पार कुछ चारागाह मिलते हैं। भारत इसे नकार देता है।

करीब डेढ़ सौ शब्दों का यह इतिहास एक ही खंभे पर खड़े चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बयां करता है। यह खंभा है भारत के साथ दुश्मनी का। पाकिस्तान कभी अमेरिका का साम्यवाद विरोधी साथी था और चीन सोवियत संघ का 'भाई' था फिर भी दोनों गले मिल गए।

इसके बाद छह दशक में यह रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। अंतर यह है कि चीन अब दुनिया की दूसरी महाशक्ति है और भारत भी पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान और चीन को एक-दूसरे की 1960 के दशक से ज्यादा जरूरत है। और अगर चीन भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को अपना मोहरा बना लेता है तो यह रिश्ता फायदेमंद है। अभी हमने इस बाजी की पहली चालें ही देखी हैं।

भारत के समक्ष दुर्लभ खनिजों की चुनौती

प्रसेनजित दत्ता

भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियां चीन द्वारा दुर्लभ खनिज मैग्नेट पर लगाई पाबंदियों का दंश महसूस करने लगी हैं। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर वाहन एवं अन्य वाहन पुर्जों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण होती हैं। चीन ने 4 अप्रैल को मैग्नेट के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी और समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार भारतीय वाहन पुर्जा एवं वाहन कंपनियों के पास इनका उपलब्ध भंडार समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। वाहन एवं सहायक उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल संभवतः चीन जाकर इस बात का पता लगाना चाहता है कि दुर्लभ खनिज की आपूर्ति की राह में रोड़ा बनने वाली नई प्रक्रियात्मक बाधाओं का बातचीत के जरिये समाधान निकल सकता है या नहीं। भारतीय ईवी कंपनियां मदद के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से भी गुहार लगा रही हैं।

मैग्नेट की आपूर्ति से जुड़ी यह समस्या स्पष्ट संकेत है कि भारत के ईवी एवं स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े बड़े लक्ष्य किस तरह आयात (ज्यादातर) पर निर्भर हैं। केवल मैग्नेट ही नहीं बल्कि भारत दुर्लभ तत्त्वों (17 खनिजों का समूह जिसे आवर्त सारणी में लैंथेनाइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है) के लिए आयात पर निर्भर है। दुर्लभ खनिज कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स (रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सहित) एवं कई अन्य के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। हालांकि, इन खनिजों की काफी कम मात्रा की जरूरत होती है मगर तब भी वे काफी जरूरी होते हैं।

भारत के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं। स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जरूरी खनिज जैसे लीथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और निकल की आपूर्ति में आने वाली बाधाएं भी भारत को पीछे धकेल सकती हैं। भारत महत्त्वपूर्ण धातु एवं खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने में कामयाब नहीं रहा है और इस बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यह स्थिति तब है जब भारत में उन खनिजों के बड़े भंडार हैं जिनका वह आयात करता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें खनिजों की खोज एवं उनके खनन में पिछले कई दशकों से सुस्त रही है और लालफीताशाही का शिकार रही हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह रही है कि सरकार ने महत्त्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की पूरी तरह अनदेखी की है। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत जब तक युद्ध स्तर पर इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आयात पर उसकी निर्भरता बनी रहेगी। हाल में सरकार ने दुर्लभ धातुओं सहित खनिजों की खोज एवं उनका खनन तेज करने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। मगर ये सब सामान्य घोषणाएं हैं जिनसे बड़ा फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए सरकार को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। लीथियम, दुर्लभ खनिजों, ग्रेफाइट और कोबाल्ट सहित कई खनिजों के प्रसंस्करण में भारत को एकदम नए सिरे से काम करना होगा।

पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर लीथियम, दुर्लभ खनिज तत्त्व, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट पर चीन की पकड़ बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और भारत सहित अधिकांश देश चीन से आपूर्ति तंत्र में आने वाले व्यवधानों के जोखिम से अछूते नहीं रहे हैं। अब वे धीरे-धीरे चीन पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं मगर इसमें कई वर्ष लग जाएंगे।

भारत जिन महत्त्वपूर्ण खनिजों का आयात करता है उनमें कुछ (जैसे कोबाल्ट और दुर्लभ खनिजों) के विशाल भंडार यहां उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि भारत में कोबाल्ट का एक चौथाई या पांचवां सबसे बड़ा अनुमानित भंडार उपलब्ध है। दुर्लभ खनिजों में दिलचस्पी बढ़ने के बाद देश के कई हिस्सों में इन तत्त्वों की खोज हुई है।

लीथियम जैसे दूसरे खनिजों की बात करें तो भारत और चीन दोनों में कहीं भी ज्ञात विशाल भंडार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में लीथियम के बड़े भंडार उपलब्ध हैं और अमेरिका में भी इसकी कमी नहीं हैं मगर चीन की इसलिए तूती बोलती है क्योंकि उसने लीथियम और कोबाल्ट दोनों के ही सबसे बड़े प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कोबाल्ट का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है मगर चीन ने वहां बड़े खदानों पर नियंत्रण कर एक मजबूत आपूर्ति व्यवस्था विकसित कर ली है। इसके साथ ही चीन ने कोबाल्ट के परिष्करण के लिए एक बड़ी प्रसंस्करण क्षमता भी स्थापित कर ली है। दुर्लभ खनिजों और ग्रेफाइट में चीन खनन और प्रसंस्करण दोनों में ही आगे है।

पिछले कई दशकों के दौरान भारत ने जरूरी खनिजों की खोज एवं उनके खनन पर काफी कम ध्यान दिया है। इन खनिजों की खोज एवं उनके खनन की जिम्मेदारी कुछ गिनी-चुनी सरकारी कंपनियों को दी गई है। हालांकि, भारत में भी अब नीलामी के जरिये निजी क्षेत्र को अनुमति देने का सिलसिला शुरू हो गया है मगर इस प्रक्रिया को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है। वैश्विक निजी कंपनियां खोज एवं अन्वेषण में बड़े जोखिम लेने के लिए अधिक मुनाफे की मांग कर रही हैं और अब तक भारत में नीलामी का ढांचा उन्हें आकर्षित करने में कामयाब नहीं लग रहा है।

यह भी सच है कि भारत ने प्रसंस्करण क्षेत्र पर भी ध्यान नहीं दिया है। प्रसंस्करण क्षेत्र पर ध्यान देने से आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सुनियोजित उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहनों (पीएलआई) योजना की जरूरत है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रसंस्करण कार्यों से देश में उत्सर्जन बढ़ता है मगर उपयुक्त नीतियों के जरिये इस समस्या का असर कम किया जा सकता है। लीथियम, कोबाल्ट या दुर्लभ खनिजों के साथ प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडारों और थोरियम (परमाणु ऊर्जा में इसकी उपयोगिता को देखते हुए) को भी खोज एवं खनन की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाना चाहिए। ये अगले कुछ दशकों में ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को नई दिशा देंगे। पहला थोरियम आधारित बिजली संयंत्र चीन में तैयार हो चुका है और अमेरिका भी थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा में शोध कर रहा है। यह खनिज भविष्य में काफी उपयोगी होगा और अच्छी बात यह है कि भारत में थोरियम का बड़ा भंडार मौजूद है।

प्राकृतिक हाइड्रोजन किसी भी हरित हाइड्रोजन परियोजना की तुलना में काफी सस्ता होगा। इसमें आत्मनिर्भरता सुनिश्चित नहीं करने की स्थिति में भारत को चीन एवं उन दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा जो इन क्षेत्रों में प्रसंस्करण एवं खनन क्षमता विकसित कर रहे हैं। वर्ष 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ता दिख रहा भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहने का जोखिम मोल नहीं ले सकता।

(लेखक बिजनेस टुडे और बिजनेसवर्ल्ड के पूर्व संपादक और संपादकीय सलाहकार संस्था प्रोजेक व्यू के संस्थापक हैं।)

आपका पक्ष

चिनाब और अंजी पुल से साल भर जुड़ी रहेगी घाटी

जम्मू-कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज अंजी ब्रिज का लोकार्पण राज्य की संपूर्ण भारत से संबद्धता और उसके विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही यह ब्रिज सामरिक आर्थिक पर्यटन आदि की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण साबित होगा। यह सिंगल आर्च ब्रिज पेरिस के एफिल टॉवर से भी लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा एवं विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला ब्रिज है। रियासी जिल में स्थित चिनाब आर्च ब्रिज 272 किलोमीटर लंबे उस रेलमार्ग का हिस्सा होगा जो कि जम्मू-कश्मीर को संपूर्ण भारत से जोड़ता है। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी के चलते जम्मू से कश्मीर की ओर जाने वाली सड़क बंद हो जाती है। लेकिन इस पुल के कारण रेलमार्ग से यह प्रांत हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहेगा। निश्चय ही इस कनेक्टिविटी से परिवहन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सर्दियों में देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट जाना घाटी के फलों की कृषि पर निर्भर व्यवसायों के लिए एक प्रमुख समस्या रही है। इस ब्रिज की मदद से सैन्य बल और जरूरी सामान को सीमाई क्षेत्रों में वर्ष भर पहुंचाया जा सकेगा। इससे भारत को पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर तनावपूर्ण संबंध वाले पाकिस्तान और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने में सहायता मिलेगी। इसकी संरचना ब्लास्ट-प्रूफ रखी गई है जो 40 किलोग्राम टीएनटी विस्फोटक को झेल सकती है। इससे पर्यटन एवं पर्यटन राजस्व दोनों में बढ़ोतरी होगी। यह दोनों ब्रिज इस सीमावर्ती राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगे।

विमलेश पगारिया, धार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी में विश्व के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज का शुक्रवार को उद्घाटन किया

नकली कृषि उर्वरकों, कीटनाशकों पर लगे रोक

नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का बढ़ता कारोबार भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। यह न केवल किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर रहा है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहा है। हाल ही में राजस्थान में कृषि मंत्री द्वारा नकली उर्वरक कारखानों पर की गई छापेमारी इस समस्या की भयावहता को उजागर करती है, जहां मार्बल स्लरी और मिट्टी से उर्वरक बनाए जा रहे थे। पूरे देश में नकली कृषि उत्पादों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। 2023-24 में जांच किए गए उर्वरक, बीज और कीटनाशक नमूनों में बड़ी संख्या में उत्पाद अमानक पाए गए, जो दर्शाता है कि प्रभावी रोकथाम के प्रयासों में कमी है। किसानों के पास असली-नकली की पहचान करने का कोई आसान तरीका नहीं होता, जिससे वे आसानी से ठगी का शिकार बन जाते हैं। यह स्थिति कृषि प्रधान राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी समान रूप से चिंताजनक है। इस काले कारोबार को रोकने के लिए बीज अधिनियम, 1966 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 जैसे कानूनों का सख्त क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। जब तक हर किसान को गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद नहीं मिलेंगे, तब तक भारतीय कृषि का भविष्य अंधकारमय ही रहेगा।

राजूराम प्रजापत, नागौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रूस के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि युद्ध में मारे गए 6,000 सैनिकों के शवों को योजनाबद्ध तरीके से यूक्रेन को सौंपे जाने के लिए मॉस्को अब भी कीव से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है। इन शवों को रेफ्रिजरेटर वाहनों के जरिये भेजा जाएगा। रूस ने सीमा पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों के सैनिकों के 1,212 शवों को पहुंचा दिया है और यूक्रेनी अधिकारियों से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है।

चिंतन

गरीबी कम हुई, अब आर्थिक सुधार की दिशा में बढ़े केंद्र

पीएम मोदी की राजग सरकार 3.0 ने आज नौ जून को एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस तरह वर्ष 2014 में भारी बहुमत से सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। मोदी सरकार के कामकाज का आकलन किया जाए तो सरकार के खाते में अनेक उपलब्धियां हैं, लेकिन साथ में कई विफलताएं भी हैं। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गरीबी कम करने में सफलता है, तो सबसे बड़ी विफलता पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को हैंडल करने के मोर्चे पर है। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच 11 वर्ष में अत्यधिक गरीबी में 21.8 फीसदी की कमी आई है। देश में अत्यधिक गरीबी दर वर्ष 2011-12 में 27.1 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 5.3 प्रतिशत रह गई है। करीब 17 करोड़ लोग बेहद गरीबी से बाहर निकले हैं। खास बात है कि गरीबी में कमी नए पैमाने के आधार पर आई है। अब रोजाना 3 डॉलर (लगभग 257 रुपये) तक खर्च करने वाले बेहद गरीब की श्रेणी में माने जाएंगे, जबकि पहले यह सीमा 2.15 डॉलर थी। काफी पहले संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग ने गरीबी से बाहर निकलने को लेकर अलग-अलग पर उत्साहजनक आंकड़े जारी किए हैं। 2024 तक भारत में करीब 5.44 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो प्रतिदिन 3 डॉलर से भी कम खर्च में जीवन जी रहे हैं। यह आंकड़ा कई विकसित देश के गरीबी के आंकड़े से कम है। गरीबी से बाहर निकलने में लोगों को सरकार की पीडीएस जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं से मदद मिली है। अब सरकार को इस आंकड़े का प्रयोग जनकल्याणकारी योजनाओं को रिमॉडल करने में करना चाहिए और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना चाहिए। कयास के विपरीत मोदी सरकार 3.0 मजबूत व आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। 400 पार के नारों के बीच जब भाजपा को वर्ष 2024 के आम चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और उसकी टीडीपी व जेडीयू पर निर्भरता हो गई तो नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू की पाला बदलने की सियासी फितरत के चलते कांग्रेस ने मोदी सरकार में उथलपुथल की संभावना को रेखांकित किया था। पर जहां नायडू व नीतीश भरोसेमंद साबित हुए, वहीं पीएम काफी सहज हैं। अब भाजपा ने अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच को नए सिरे से तैयार करने के लिए फिर से काम शुरू किया है। मोदी सरकार ने महिला केंद्रित व नीत विकास को बढ़ावा देकर अपने लिए नया जनाधार तैयार किया है। डिजिटल सेक्टर में सरकार ने काफी क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। हालांकि विनिर्माण सेक्टर में ग्रोथ चुनौती बनी हुई है। नक्सलवाद को कम करने में मदद मिली है, पर आतंकवाद के खिलाफ बहुत कुछ करना बाकी है। विदेश नीति की धार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुंद हुई है, इसे तुरंत पटरी पर लाने की जरूरत है। अमेरिका से रिश्ते बराबरी के स्तर पर रखने चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार जरूरी हैं, रक्षा क्षेत्र को मॉडर्न वार टेक्नीक से लैस करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक, न्यायिक और पुलिस सुधार की दिशा में बढ़ने की जरूरत है। सरकार को कृषि, सेवा क्षेत्र के साथ उद्योग क्षेत्र पर केंद्रित रहना चाहिए, आर्थिक सुधार के अगले चरण को लागू करना चाहिए, विभिन्न करों का सरलीकरण करना चाहिए। अपनी सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट करना चाहिए। विकसित भारत के लक्ष्य सभी मानकों पर विकास से हासिल होंगे, केवल चौथी अर्थव्यवस्था के आंकड़े भर से नहीं।

मस्क-ट्रंप महासमर

प्रो. आर.के. जैन

स्पेसएक्स से व्हाइट हाउस तक, कौन किसे मात देगा

एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है, जो न केवल दो दिग्गजों एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का टकराव है, बल्कि यह सत्ता, पूंजी और तकनीक का वह महासमर है, जो दुनिया को नई दिशा दे सकता है। यह दो तूफानों का मिलन है। एक ओर मस्क, जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों से भविष्य को फिर से परिभाषित किया, दूसरी ओर ट्रंप, जिनका राजनीतिक प्रभाव वैश्विक समीकरणों को हिलाने की ताकत रखता है। इनके बीच की यह लड़ाई अब केवल शब्दों की जंग नहीं रही, यह टेस्ला के शेयरों की गिरावट, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और वैश्विक सत्ता के गलियारों तक को हिला रही है। दोनों के पास दुनिया के सबसे बड़े मंच हैं, और अब ये मंच एक-दूसरे के खिलाफ खतरनाक हथियार बन चुके हैं। यह टकराव एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो भविष्य की दुनिया को आकार दे सकता है। इस जंग की शुरुआत तब हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क की कंपनियों, खासकर स्पेसएक्स को मिलने वाली अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी और अनुबंधों को खत्म करने की धमकी दी। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर लिखा - बजट बचाने का सबसे आसान तरीका मस्क की सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को रद करना है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, स्पेसएक्स नासा के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) तक अंतरिक्ष यात्रियों और सामग्री पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। ट्रंप की यह धमकी मस्क के कारोबारी साम्राज्य की रीढ़ तोड़ने की कोशिश हो सकती है। इसका असर तुरंत दिखा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को टेस्ला के शेयर 14% तक गिर गए, जिससे निवेशकों में खलबली मच गई। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि मस्क की कंपनियां इस जंग में कितनी जोखिम में हैं। एलन मस्क, जिन्हें दुनिया एक दूरदर्शी नवप्रवर्तक के रूप में जानती है, ने ट्रंप की इस चुनौती को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जवाबी हमला बोलते हुए ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की और अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान के कार्यों को तेज करने की बात कही। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह यान अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अपरिहार्य हैं। मस्क का यह कदम ट्रंप को यह स्पष्ट संदेश देता है कि वे किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं। इस टकराव के परिणाम मस्क और ट्रंप तक सीमित नहीं हैं। मस्क के पास असीमित संसाधन हैं, जिनका उपयोग वे राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार, मस्क ने दावा किया कि वे "सचमुच एक बड़ा बम गिरा रहे हैं," जिससे संकेत मिलता है कि वे अगले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के विद्रोही उम्मीदवारों को फंडिंग दे सकते हैं। यह कदम ट्रंप की राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर, ट्रंप के पास सरकारी मशीनरी का नियंत्रण है, जिसका उपयोग वे मस्क की कंपनियों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि ट्रंप अपनी धमकी को अमल में लाते हैं, तो स्पेसएक्स के अनुबंधों पर असर पड़ सकता है, जिसका प्रभाव अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम और वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग पर होगा। आर्थिक प्रभाव पहले ही सामने आ चुका है। टेस्ला के शेयरों की गिरावट से निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है, जैसा कि रॉयटर्स ने उल्लेख किया। स्पेसएक्स के अनुबंधों पर खतरा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है। यदि मस्क अपने ड्रैगन यान के कार्यों को बंद करते हैं, तो नासा को वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढनी पड़ेगी, जो एक जटिल और महंगा कदम होगा। यह जंग तकनीक और सत्ता के बीच संबंधों को उजागर करती है। मस्क की कंपनियां निजी क्षेत्र की ताकत का प्रतीक हैं, जबकि ट्रंप सरकारी शक्ति का चेहरा हैं। यह टकराव यह सवाल उठाता है कि क्या निजी कंपनियां सरकारों को चुनौती देने की ताकत रख सकती हैं? यह जंग अब केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वैश्विक रण है, जो तकनीक, पूंजी और सत्ता के भविष्य को परिभाषित करेगा। दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि यह टकराव कहां तक जाएगा। क्या मस्क अपने संसाधनों के दम पर ट्रंप को पछाड़ देंगे, या ट्रंप की सरकारी मशीनरी मस्क के साम्राज्य को झुका देगी? यह युद्ध न केवल इन दो दिग्गजों की साख का सवाल है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार और राजनीतिक समीकरणों को नया आकार दे रहा है। यह एक ऐसी आंधी है, जो दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि सत्ता और पूंजी का यह महासंग्राम हमें किस भविष्य की ओर ले जाएगा। यह टकराव एक नई कहानी लिख रहा है, एक ऐसी कहानी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

11 वर्ष

उमेश चतुर्वेदी

मोदी सरकार से अभी और हैं उम्मीदें

अगर जनता ने मोदी पर लगातार भरोसा जताया तो इसकी वजह है उनकी कार्यशैली। 2014 की जीत में लोगों की उम्मीदें थीं। इन उम्मीदों की वजह विकास का उनका गुजरात मॉडल रहा। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उन्होंने जो कोशिश की, 2019 में उसे जनता का भरपूर साथ मिला। उनमें भरोसे की वजह ही थी कि उन्हें और ज्यादा भारी बहुमत से रायसीना की पहाड़ियों के बीच शपथ लेने का मौका मिला, लेकिन भारत जैसे बहुभाषी, बहुरंगी देश में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आर्थिक आय की असमानता में संतुलन आज की बड़ी जरूरत है। भारत को यूरोप की तर्ज पर विकसित करने, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की जरूरत अब भी है।

भारतीय परंपरा में ग्यारह की संख्या शुभ मानी जाती है। पारिवारिक और धार्मिक समारोहों में शगुन के रूप में ग्यारह रुपये की भेंट देने की परंपरा इसी वजह से रही है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को शगुन काल भी कह सकते हैं। ग्यारह साल का वक्त कम नहीं होता। इस दौरान पीढ़ी भी बदल जाती है। ऐसे में इस पूरे दौर का जो मूल्यांकन होगा, उसे पीढ़ीगत नजरिए से भी देखना होगा, क्योंकि हर नई पीढ़ी का नजरिया बुजुर्गों से अलग होता है। इन अर्थों में देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और उनका कार्यकाल अनूठा लगेगा। मोदी और उनकी कार्यशैली पुरानी पीढ़ी को भी पसंद हैं और नई पीढ़ी के तो प्रेरक हैं ही। इसकी वजह है, उनकी अद्भुत संप्रेषण कला, जिसके जरिए वे सीधे लोगों के दिलों से जुड़ जाते हैं। नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल के बाद लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की सूची में मोदी पहुंच चुके हैं। किसने सोचा था कि 1984 में महज दो लोकसभा सीटों तक सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी लगातार तीन संसदीय चुनावों में बाजी मारती रहेगी। इसमें शक नहीं कि यह उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नेतृत्व से ही हासिल हुई है।

अगर जनता ने मोदी पर लगातार भरोसा जताया तो इसकी वजह है उनकी कार्यशैली। 2014 की जीत में लोगों की उम्मीदें थीं। इन उम्मीदों की वजह विकास का उनका गुजरात मॉडल रहा। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उन्होंने जो कोशिश की, 2019 में उसे जनता का भरपूर साथ मिला। उनमें भरोसे की वजह ही थी कि उन्हें और ज्यादा भारी बहुमत से रायसीना की पहाड़ियों के बीच शपथ लेने का मौका मिला। इस कड़ी में देखें तो 2024 में बहुमत से दूर रह जाना खटकता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि दस साल के कार्यकाल में आकांक्षाओं का उद्दाम होना स्वाभाविक है और सारी आकांक्षाओं का पूरा कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए कुछ लोग हो सकता है निराश भी रहे हों, जिसका असर चुनाव नतीजों पर दिखा। मोदी के कार्यकाल की कई उपलब्धियां हैं। मोटे तौर पर सबसे बड़ा जो बदलाव दिखता है, वह है कि इस पूरी अवधि में देश में कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं दिखा। ऐसा नहीं कि सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो गया है। जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्र की सोच में पारंपरिक भ्रष्टाचारी गंध है। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह हुआ है कि भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसता रहा है। इस शिकंजे से न तो अधिकारी बाहर हैं और न ही राजनेता। तकरीबन पूरे देश में सरकारी तंत्र के कामकाज का अपना तरीका रहा है, उसकी अपनी गति रही है। लेकिन मोदी के नेतृत्व में अब कामकाज का तरीका बदला है। इसे समझने के लिए हाल ही में हुए दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के उद्घाटन समारोह को देख सकते हैं। चिनाब पुल के उद्घाटन के वक्त जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इस परियोजना की शुरुआत हुई, तब वे आठवीं में पढ़ रहे थे, अब वे पचपन साल के हैं और अब जाकर यह पूरा हो पाया है। मोदी के ग्यारह साल के शासन में तंत्र के कामकाज का तरीका बदला है। अब वह ज्यादा अनुशासित और लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करने को लेकर ज्यादा प्रतिबद्ध हुआ है। नौकरशाही में संजीदापन तो आया है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में नौकरशाही पर तंत्र के दूसरे अंगों की बजाय ज्यादा भरोसा बढ़ने की वजह से तटस्थ लोगों की नजर

में ब्यूरोक्रेसी कई मामलों में बेलगाम भी हुई है। इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय मोदी सरकार अपनी ग्यारहवीं सालगिरह मनाने जा रही है, उसी वक्त विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान देश में गरीबों की संख्या 27.1 फीसद से घटकर 5.3 प्रतिशत रह गई है। यह तब हुआ है, जब विश्व बैंक ने गरीबी रेखा के लिए तीन डॉलर प्रतिदिन खर्च की सीमा कर दी है, जबकि इसके पहले यह सीमा 2.15 डॉलर प्रतिदिन थी। जाहिर है कि इसके पीछे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न योजना के साथ ही उज्ज्वला, मुद्रा आदि योजनाओं की कामयाबी रही है। मोदी सरकार की कई उपलब्धियां हैं।

देश ने मेडिकल कॉलेजों के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। साल 2014 में जहां इन कॉलेजों की संख्या 387 थी, वह 2025 में बढ़कर 780 हो गई है। इसी तरह एमबीबीएस की सीटें भी 51,348 से बढ़कर 2024 में 1.18 लाख हो गई हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में बीजेपी के दावे के अनुसार, 17.1 करोड़ नई नौकरियां निकलीं। इस दौरान स्टार्टअप से 1.61 लाख युवाओं को रोजगार मिला। बीजेपी के दावे के अनुसार, सरकार की कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 2.27 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग मिल चुकी है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक करीब दस करोड़ 28 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के तहत करीब 52 करोड़ ऋण खाते खोले गए हैं, यानी करीब इतने लोगों को कर्ज मिल चुका है। इससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास, जन-धन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने देश में बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। देशभर में बारह करोड़ शौचालयों का निर्माण भी मामूली उपलब्धि नहीं है। मोदी सरकार की इन योजनाओं के चलते देश में बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव डीबीटी यानी सीधे कैश ट्रांसफर की योजनाओं ने ग्रामीण और कमजोर वर्गों तक शासन की योजनाओं की पहुंच बढ़ाई है।

जापान को पछाड़कर भारत हाल ही में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका भी श्रेय मोदी सरकार को ही जाता है। देश सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक मोर्चे पर लगातार विकास कर रहा है। इस विकास में परंपरा, आधुनिकता और वैश्विक जुड़ाव का अद्भुत समावेश नजर आता है। मोदी सरकार की ही देन है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल लोक, मां कामाख्या मंदिर, राम मंदिर अयोध्या, केदारनाथ धाम और जूना सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। राममंदिर के निर्माण की उपलब्धि ही मोदी सरकार के खाते में जाती है। करतारपुर कॉरिडोर के चलते पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब भारतीय सिखों के लिए सुलभ हुआ। इसी दौरान राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान देने की दिशा में प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जलियांवाला बाग स्मारक जैसे संस्थान बनाए गए।

मोदी सरकार के ही कार्यकाल में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनी और उसे लागू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर उसका ही प्रतीक है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा, 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे कदम मोदी सरकार ने ही उठाए। नक्सलवाद पर लगाम भी तेजी से इसी दौर में लगा। मोदी सरकार की उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी है। लेकिन भारत जैसे बहुभाषी, बहुरंगी देश में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आर्थिक आय की असमानता में संतुलन आज की बड़ी जरूरत है। भारत को यूरोप की तर्ज पर विकसित करने, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की जरूरत अब भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में भारत इन उपलब्धियों को भी हासिल करने में सफल रहेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

मनुष्य हो तो पहले प्राप्त करो ज्ञान

संकलित

दर्शन

मन में पहली जिज्ञासा यही होती है कि एक साधक होने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। क्या साधक में आयु, ज्ञान या फिर चरित्र संबंधी योग्यता होनी चाहिए। ज्ञानीजन कहते हैं कि एक साधक के भीतर मनुष्यता होना जरूरी है, तभी वह अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा पाएगा। मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य ज्ञान प्राप्त करना है। व्यक्ति को सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और धर्म साधना भी करनी चाहिए। इसके साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी देखना चाहिए। यह मनुष्य की साधना का एक चरण है। पार्वती ने शिव से पूछा, 'साधक बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है?' शिव ने उत्तर दिया, 'जब जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप मानव रूप धारण कर लेते हैं, तब वे साधना करने के योग्य हो जाते हैं।' पार्वती द्वारा रखा गया अगला प्रश्न था, 'साधना करने के लिए मनुष्य में आयु, योग्यता, चरित्र आदि जैसी कौन-सी योग्यताएं होनी चाहिए?' इस पर शिव के उत्तर को इस तरह समझा जा सकता है कि उम्र के संबंध में यह कहना उचित होगा कि मानव जीवन में मूल रूप से चार चरण होते हैं। पहले चरण में मनुष्य का पहला कर्तव्य ज्ञान प्राप्त करना और धर्म साधना करना है। दूसरे चरण में, व्यक्ति को सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और धर्म साधना करनी चाहिए। तीसरे चरण में, किसी भी शेष पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखना चाहिए और धर्म साधना करनी चाहिए। अंत में यानी चौथे चरण में जब मानव शरीर सांसारिक कर्तव्यों को निभाने में अक्षम हो जाता है, तो व्यक्ति को अकेले धर्म साधना करनी चाहिए।

आप पर कैसे बरसेगी कृपा

संकलित

प्रेरणा

कृपा कोई अमूर्त, गैरहाजिर विचार या कल्पना नहीं है पर ये एक जीवित शक्ति है, जिसे हम अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी शक्ति, बुद्धि और जानकारी से जो कुछ भी कर सकते हैं, वह सब बहुत सीमित है। अगर आप कृपा की खिड़की को खोल सकें तो जीवन ऐसे अद्भुत तरीके से चलेगा, जो संभव होने की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके सामने हर जगह यह सवाल है, 'मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं?' पर, यह कोई करने वाली चीज नहीं है। आपके अंदर, अगर कोई खाली जगह है, जहां आपके विचार और पूर्वाग्रह, आपकी भावनाएं और विचारधाराएं अंदर न आ सकें, तो आपके जीवन में कृपा एक प्रबल शक्ति की तरह होगी। अगर आप अपने ही विचारों, अपनी ही भावनाओं और कल्पनाओं आदि से भरे हुए हैं तो कृपा आपके आसपास बहते हुए भी, आपके अंदर कुछ नहीं होगा। ज्यादातर लोगों के जीवन के साथ यही त्रासदी है कि उनके आसपास एक जबर्दस्त संभावना हमेशा बनी रहने के बावजूद वे उसे पूरी होने नहीं देते। सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए विचार, फोकस और करने के तरीके यही हैं कि आपके व्यक्तित्व को खत्म कर दिया जाए, जिससे आपके अंदर कोई खाली उपस्थिति बने और वह आपके लिए कृपा और संभावना का ऐसा प्रवेश द्वार बने, जिसके बनने की संभावना के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। सवाल यह नहीं है कि आप पर कृपा काम कर रही है या नहीं? वह तो कर ही रही है, वरना आपका अस्तित्व ही संभव नहीं।

अंतर्मन

आज की पाती

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती हो

नाबालिग वाहन चालकों के लिए सख्ती होना चाहिए। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो इसके लिए सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस कानून के तहत लगभग 25 हजार जुर्माना और लगभग तीन साल की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि सरकार और प्रशासन इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। स्कूलों में इसके लिए बच्चों को जागरूक भी किया जाए और स्कूलों से विद्यार्थियों के माता-पिता को इसके लिए नोटिस भी भेजे जाए कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। दोपहिया वाहन एक्सीडेंट का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर एक्टिवा चलाते समय हैलमेट का प्रयोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, न कि चालान के डर से। *-कृष्णा सिंह ठाकुर, रायपुर*

ट्रेंड

किसानों के इनोवेशन

हमारे वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च और इनोवेशन किया है, और इनोवेशन से फार्मर को भी जोड़ा है, उसका परिणाम तो आज देख रहा हूं। हमारे किसानों ने भी अलग-अलग ढंग के इनोवेशन किये हैं।
- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

खुले में शौच से मुक्ति

हर घर में शौचालयों के निर्माण से नारी शक्ति के लिए सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ। 11 वर्षों में, भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया, 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय और 2.49 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बने हैं।
- हिमंत बिस्व शर्मा, सीएम, असम

जनता का भरोसा जीता

सिर्फ एक साल में हमने दिखा दिया है कि एक सच्ची जनता की सरकार कैसी होती है। बीजेडी के कई सालों के झूठे वादों और आकर्षक विज्ञापनों के बाद, ओडिशा के लोगों ने बदलाव को चुना और हमने उस भरोसे को कार्रवाई से पूरा किया है।
- मोहन चरण माझी, सीएम, ओडिशा

बिजली कटौती शुरू

भाजपा की राजस्थान में सरकार बनने का एक वर्ष पूरा होने पर प्रचार किया गया कि प्रदेश अब बिजली में सरप्लस स्टेट हो गया है लेकिन गर्मी बढ़ते ही हर जगह बिजली कटौती शुरू हो गई। बिजली वितरण का ढांचा चरमराया है जिससे आमजन त्रस्त है।
-अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

करंट अफेयर

कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 6,000

देश में पिछले 48 घंटे में कोविड-19 के 769 नये मामले सामने आए, जिसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या छह हजार के पार पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। मंत्रालय के अनुसार, केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, उसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली का स्थान है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्र 'मॉक ड्रिल' आयोजित कर रहा है और सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भारत में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 6,133 है और पिछले 24 घंटों में छह और संक्रमितों की मौतें हुई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण थे और वे घर पर ही उपचार के बाद ठीक हो गए। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और तैयारी के उपायों का आकलन करने के लिए आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, आपात प्रबंधन प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठकें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में दो जून और तीन जून को हुई।

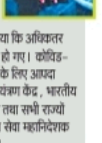

ऑफ बीट

ऑक्सफोर्ड में पढ़ने भारतीय छात्रों को रोड्स छात्रवृत्ति

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले रोड्स स्कॉलरशिप ट्रस्ट ने 2028 से भारतीयों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या को देश की जनसंख्या के अनुरूप बढ़ाने की योजना बनाई है। अगले साल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदनों की घोषणा से पहले, भारत आए ट्रेनर ने साक्षात्कार में बताया कि वर्तमान में भारतीय अभ्यर्थियों को सालाना छह छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अब प्राथमिकता उन स्थानों के लिए कुछ अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान करने की है, जहां जनसंख्या के अनुपात में विद्वानों की संख्या अधिक हो सकती है और भारत उन देशों में से एक है। इसलिए, हमारे पास भारत के लिए प्रति वर्ष छह छात्रवृत्तियां हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में डेढ़ अरब लोग हैं, इसलिए अधिक छात्रवृत्तियां होनी चाहिए। रोड्स हाउस के अंतरिम 'वॉर्डन' ने कहा, हम अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के लिए धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की फीस का भुगतान करने तथा छात्रों के जीवन-यापन के व्यय का भुगतान करने के लिए निधि में धन की आवश्यकता है। छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए चीन और अफ्रीका जैसे अन्य देश भी प्राथमिकता में हैं।

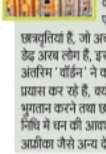

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

49 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली महानदी और इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली परियोजना के तहत, जिससे लगभग सात लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा विकसित की जा सकेगी।

आरबीआइ की द्विमासिक मुद्रा नीति

आर्थिकी को गति देने का प्रयास

आरबीआइ ने छह जून को रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे छह प्रतिशत की दर से नीचे लाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक अब देश की विकास दर को गति देने पर जोर दे रहा है। आरबीआइ के गवर्नर ने रेपो रेट में कटौती की इस घोषणा को आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने वाला कदम बताया है। इसलिए यह उम्मीद जगी है कि आरबीआइ की इस पहल से देश की आर्थिकी की गति और तीव्र होगी

प्रह्लाद सबनानी
आर्थिक मामलों के जानकार

भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया घोषित मुद्रा नीति से अर्थव्यवस्था की गति तेज होने की जगी है उम्मीद। फाइल

वैश्विक अर्थव्यवस्था जटिल होती जा रही है। कई देशों में आर्थिक गतिविधियों पर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से नित नई घोषणाएं की जा रही हैं। कभी टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है तो कभी इसे लागू करने की तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है, तो कभी इसमें कटौती की बात की जा रही है। कुल मिलाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एवं कारोबारी व अब तक ट्रंप के राजनीतिक सहयोगी रहे एलन मस्क के बीच मतभेद होने के कारण वे एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का इन सबसे बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, कंपनियों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी पर विचार किया जा रहा है एवं आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ रही है। दूसरी ओर, रूस व यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच भी युद्ध जारी ही है। चीन एवं अमेरिका के बीच संबंधों में आई खटास भी कम होने का नाम नहीं ले रही है।

इन वैश्विक घटनाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था नित नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। भारत में नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रति कटिबद्ध हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के उपक्रम एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां देश के आर्थिक विकास को गति देने में अपने प्रयास निरंतर तेज करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छह जून को द्विमासिक मुद्रा नीति की घोषणा करते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक, रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे छह प्रतिशत की दर से नीचे लाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है। कैलेंडर वर्ष 2025 में रेपो दर में यह लगातार तीसरी कटौती की गई है एवं कुल मिलाकर रेपो दर में 100 आधार बिंदुओं की कमी की जा चुकी है।

फरवरी, 2025 एवं अप्रैल, 2025 में घोषित की गई मुद्रा नीति के माध्यम से रेपो दर में दोनों बार 25 आधार बिंदुओं की कमी की गई थी। दरअसल रेपो दर उस दर को कहते हैं, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण उपलब्ध कराता है एवं विभिन्न बैंक रेपो दर को आधार दर बनाते हुए इस दर पर कुछ आधार बिंदु (जमाराशि की लागत एवं लाभ की राशि का समायोजन करते हुए) जोड़ते हुए, ब्याज की दर पर अपने ग्राहकों को ऋणराशि उपलब्ध कराते हैं। चूंकि भारत में कृषि विकास दर गति पकड़ रही है, इस वर्ष मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 65 डालर के आसपास रहने की संभावना है, अतः भारत में मुद्रास्फीति की दर 2025-26 में चार प्रतिशत के सहनीय स्तर से नीचे रहने का अनुमान है।

वहीं दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात में सीधे 100 आधार बिंदुओं की कमी करते हुए इसे चार प्रतिशत की दर से घटाकर तीन प्रतिशत की दर पर ला दिया है। इससे भारत में बैंकों के पास दिसंबर 2025 तक 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध हो जाएगी एवं सिस्टम में तरलता बढ़ जाएगी। नकद आरक्षित अनुपात उस अनुपात को कहते हैं, जिस पर विभिन्न बैंकों को अपने मांग एवं जमा देयताओं की राशि पर इस अनुपात की दर से नकदी राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करानी होती है। अतः यह राशि इन बैंकों की पहुंच से बाहर हो जाती है एवं ऋण के रूप में इसे बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यदि नकद आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है तो बैंकों के पास यह राशि ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। इससे स्पष्टतः बैंकों की लाभप्रदता में सुधार होता है।

ब्याज दरों में कमी : भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त महत्वपूर्ण दोनों निर्णयों से वैश्विक स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बीच भारत में उत्पादों की आंतरिक मांग उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋणराशि पर ब्याज दरों को कम करेंगे। इससे विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण आदि सस्ते होंगे और अब प्रति माह ग्राहकों द्वारा इन ऋणों पर अदा की जाने वाली मासिक किस्त की राशि में कमी आएगी और इन नागरिकों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने लगेगी, जिसे वे अन्य पदार्थों को खरीदने में खर्च कर सकेंगे। साथ ही, ऋण पर ब्याज राशि कम होने से विभिन्न उत्पादक कंपनियों की लाभप्रदता में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें अब बैंकों से लिए गए ऋण पर कम ब्याज देना होगा। लाभप्रदता में होने वाली इस अतिरिक्त वृद्धि के चलते ये कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के बारे में गंभीरता से विचार करेंगी, क्योंकि उत्पादों की होने वाली मांग में वृद्धि की पूर्ति जो करनी है।

बेहतरीन मौद्रिक नीति : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हालिया घोषित मौद्रिक नीति को अर्थशास्त्रियों एवं बैंकिंग जगत के विशेषज्ञों द्वारा हाल के वर्षों में घोषित की गई सबसे बेहतरीन मौद्रिक नीति माना जा रहा है। इस मौद्रिक नीति को भारत के शेयर बाजार ने भी छह जून को त्वरित सकारात्मक उत्तर दिया और निफ्टी एवं सेंसेक्स में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। ब्याज दरों से जुड़े क्षेत्रों विशेष रूप से बैंकिंग, रियल एस्टेट एवं आटो क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। दरअसल अधिकतर अर्थशास्त्री रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की उम्मीद कर रहे थे, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 आधार बिंदुओं की कमी की घोषणा करते हुए अपनी आक्रामक नीति का परिचय दिया है। अतः रेपो दर में उम्मीद से अधिक कटौती होने पर निवेशकों का भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से वे कंपनियां जो घरेलू मांग एवं ऋण पर निर्भर रहती हैं, उन पर भरोसा बढ़ा है।

भारतीय कंपनियों की लाभप्रदता एवं उत्पादों की बिक्री में लगातार हो रहे तेज सुधार के चलते इन भारतीय कंपनियों की साख अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ेगी। ब्याज दरों में निरंतर की जा रही कमी के चलते इन कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन लागत भी कम होगी जिससे इन कंपनियों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महंगाई दर में आई कमी एवं विकास दर में आई सुस्ती को देखते हुए रेपो दर एवं नकद आरक्षित अनुपात में आक्रामक रूप से की गई कटौती को एक सक्रिय निर्णय कहा जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में खपत एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी, उद्योग जगत अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपने पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर विचार करेगा। चूंकि भारत में मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है, अतः आरबीआइ ने देश में विकास दर को बढ़ाने को प्राथमिकता दी है।

आत्मबल के सहारे आगे बढ़ता राष्ट्र

प्रो. महेश चंद गुप्ता

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने उसे वैश्विक निवेश और तकनीकी साझेदारी का केंद्र बना दिया है। कश्मीर में बना चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग कौशल का आश्चर्यजनक नमूना है। वहीं, भारत में अब राफेल लड़ाकू विमानों के मुख्य ढांचे का निर्माण हैदराबाद में किया जाएगा जो कि 'मेक इन इंडिया' पहल की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और फ्रांस की संबंधित एविएशन कंपनी के बीच हुआ एग्रीमेंट बताता है कि भारत अब केवल आयातक नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादों का निर्माता और निर्यातक भी बन रहा है। डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की बड़ी उपलब्धि है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश देने की नीति अपनाकर बड़ा बदलाव किया है। इससे प्रतिस्पर्धा, नवाचार व गुणवत्ता को बढ़ावा मिला है।

उम्मीद है, भारत अगले दस वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ देगा। इतना ही नहीं, स्वदेशी तकनीक और स्टार्टअप्स के जरिए भारत अपने डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। भारत ने ऊर्जा, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी बन रहा है। सरकार की योजनाओं और निजी निवेश के समन्वय से भारत ऊर्जा निर्यातक देश बनने की राह पर है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण भी शुरू हो चुका है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे देश को इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एआइ में भी आत्मनिर्भरता हासिल होगी।

हालांकि अभी देश के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए भारत आगे बढ़ने को दृढ़ संकल्पित है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना केवल एक राजनीतिक घोषणापत्र नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। इसके लिए नीति, नीयत और नागरिक तीनों का सहयोग आवश्यक है और यही तीनों आज एकजुट होकर भारत को आगे ले जा रहे हैं। भारत अब उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां से वह केवल अपनी समस्याएं सुलझाने के साथ ही वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी भागीदारी निभा रहा है। यही है नया भारत, जो आत्मनिर्भर, शक्तिशाली, तकनीकी रूप से उन्नत और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने को तत्पर है। यह उस नए भारत की झलक है जो आत्मविश्वास, एकता, नवाचार और नेतृत्व की भावना से परिपूर्ण है।

(लेखक प्रख्यात शिक्षाविद हैं)

खरी-खरी

पुलिस गिरफ्त में घोड़ा

प्रभुनाथ शुक्ल

हमारे जीवन में संगत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगत हमें अच्छा बनाती है, बुरी संगत बुरा बनाती है। संगत का प्रभाव हमारे कर्म पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव ईसान के साथ जानवरों में भी देखा गया है। ईसान अपना काम निकालने के लिए बेगुनाह जानवरों को भी नहीं छोड़ता है। अपने किए बुरे कर्मों का फल जानवर पर मढ़ देता है। जबकि निर्दोष जानवर आदमी के विश्वास में बेमतलब मारा जाता है। आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि जानवरों को भी नहीं बख्श रहा है। अब बिहार को ही ले लीजिए, बेचारे घोड़े का क्या दोष, शराब की तस्करी में मालिक ने अपना गुनाह घोड़े पर लाद दिया। राज्य की बहादुर पुलिस शराब तस्कर को तो पकड़ नहीं पाई, उल्टे घोड़े को गिरफ्तार कर लिया।

अब बेचारा घोड़ा भी क्या सोचता होगा कि ईसान की साजिश में हम कहां फंसे। बेचारे घोड़े को समझ नहीं आ रहा है कि इस साजिश से कैसे निकला जाए। बेचारा अपने मालिक से तो वह कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है। मालिक तो भाग निकला और फंस गया घोड़ा। फायदा मालिक ने कमाया और दोष उस पर मढ़ दिया। बिहार पुलिस भी कितनी बहादुर है। पुलिस गुनहगारों को पकड़ने के बजाय बेगुनाह घोड़े को पकड़ती है।

बिहार पुलिस के लिए घोड़े की गिरफ्तारी अब सिरदर्द बन गई है। उसके चारा-पानी की व्यवस्था भी पुलिस को करनी है। राज्य की पुलिस भी इस बला से परेशान है। कम से कम तस्कर को पकड़ती तो उसका भला भी होता, लेकिन घोड़े को पकड़ कर तो उसने मुसीबत मोल ले ली है। घोड़ा तो शराब पीएगा नहीं, उसे तो चने और भूसे-घास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिहार पुलिस अब ऐसे लोगों को खोज रही है जिन्हें घोड़े को सुपुर्दगी में सौंप दिया जाए। कम से कम घोड़ा तो सुरक्षित रहे, वरना घोड़े को कुछ दिक्कत हुई तो पुलिस की मुसीबत भी बढ़ जाएगी। उधर घोड़ा भी मस्त है, जितने दिन वह पुलिस अभिरक्षा में रहेगा, आराम करेगा और भोजन तो मिलेगा ही। वरना मालिक तो उस पर बोझ ढोता और शराब की तस्करी करता। शराब के बहाने ही सही, परंतु उसे आराम तो मिल गया।

X पोस्ट

भारत में अचानक कुछ लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद आने लगे है। ये वही लोग है जिन्हें कुछ दिनों पहले तक ट्रंप फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

गरीब लोगों को मुफ्त में पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सरकार देती है। सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं को स्वास्थ्य सेवा सरकार मुफ्त देती है। मध्य वर्ग खुद की सुरक्षा के लिए बीमा खरीदता है और इसके ऊपर 18 प्रतिशत जीएसटी भी देता है। लगता है देश में सबसे ज्यादा शोषण मध्य वर्ग का होता है।
मनीष पांडेय@ManishPandeyLKW

विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की गरीबी दर बढ़कर 44.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। वहीं इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर घटकर 5.3 प्रतिशत रह गई है। यदि दुनिया यह समझ पाती कि पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता गरीबी के बजाय आतंकवादियों को पालने पर खर्च होती है, तो स्थिति भिन्न होती।
प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या एलन मस्क की नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप को महंगी पड़ सकती है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आप मानते है कि भारत में गरीबी दर में बड़ी गिरावट का कारण मोदी सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रम है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बनना चाहे ट्रंप जी दुनिया के सरपंच,
किंतु हाथ से जा रहा खुद अपना ही मंच।
खुद अपना ही मंच मस्क से कर ली खटपट,
लेकर भाव रसाय गांठ भी टूटी चटपट।
भारी दिखता आज ट्रंप को फिर से चुनना,
अब खुद प्रेसीडेंट मस्क जी चाहें बनना!
- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

पड़ाव पर बांकेबिहारी मंदिर कारिडोर

भारतीय बसंत कुमार
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर कारिडोर को लेकर वृंदावन में शुरू हुए स्थानिक विरोध की ऊष्मा धीरे-धीरे कम होगी। गोस्वामी समाज के अंदर से ही एक धड़ा कारिडोर निर्माण के समर्थन में आ रहा है, न्यास गठन को लेकर सर्वाधिक जिच है। सेवायतों को आशंका है कि न्यास गठन के बाद उनका राग-भोग-सेवा का अधिकार छीन लिया जाएगा और मंदिर सरकार के हाथ में चला जाएगा। सरकार के प्रतिनिधि लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस जिच का पटाक्षेप होगा।

किसी भी तीर्थ क्षेत्र के विकास से सर्वाधिक लाभ स्थानीय लोगों को ही होता है। वर्तमान संख्या के सापेक्ष आगत लोगों की संख्या में कई गुना वृद्धि होती है। जो लोग आएंगे उनके आगमन से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लाभ का हाल जानना हो तो 2021 में कारिडोर बनने के बाद बनारस के होटल वालों, नाव-रिक्शा-खोमचा वालों, माला-फूल-प्रसाद बेचने वालों या फिर छोटे-बड़े सभी प्रकार के दुकानदारों से कोई बात करके देखें। कितने मुदित हैं। ऐसा नहीं है कि श्रीकाशी विश्वनाथ कारिडोर बनने के समय गतिरोध नहीं हुआ था, पर लोगों ने प्रशासन पर भरोसा किया। इसका परिणाम है कि कारिडोर के निर्माण के बाद भी न तो किसी के मुआवजे का कोई विवाद है और न ही कोई मामला कोर्ट में लंबित है। कारिडोर से जन्मी नई आर्थिकी से पूरी काशी आह्लादित है।

मंदिर को निश्चित रूप से परमार्थ सेवा का उदाहरण बनना चाहिए। देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहां मंदिर के पैसे से कहीं अस्पताल चल रहा तो कहीं स्कूल-कालेज, अनाथालय और धर्मशाला। मंदिर से केवल परिवार चले, इससे अलग समाज चलने की चिंता करनी चाहिए। ट्रस्ट के रूप में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सेवाभावी संकल्प से दृष्टि मिलती है। निःशुल्क अन्न क्षेत्र, संस्कृत विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक और वस्त्र के साथ अस्पताल में मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था का अनुपम उदाहरण ट्रस्ट के सेवा संकल्पों में समाहित है।

वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर। फाइल

श्रीराधा-कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन के अलौकिक स्वरूप को निखारने की तैयारी में सरकार पूरे जोर से लगी है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी वहां जाकर सेवायतों और अन्य लोगों से मुलाकात कर उनके मन की भ्रांतियां दूर करने में जुटे हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी लगातार कारिडोर के पक्ष में जनमानस को तैयार करने में जुटी हैं। बांकेबिहारी मंदिर में हर दिन काफी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। विशेष फलदायी दिनों पर दर्शन के लिए पहुंचे लाखों लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। 19 अगस्त, 2022 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर यहां रात दो बजे होने वाली मंगला आरती में भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई थी जिसमें दो श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। इससे ठीक दो दिन पहले मथुरा निवासी समाजसेवी अनंत शर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर पूछा था कि वृंदावन के मंदिरों में बढ़ती भीड़ को लेकर सरकार के पास क्या प्रबंध है? तब सरकार ने पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह और अलीगढ़ के तत्कालीन मंडलायुक्त गौरव दयाल की कमेटी बनाई थी। कमेटी के सुझाव में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की तरह यहां भी कारिडोर बनाने का प्रकल्प आया था।

सेवायतों की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची अपील के बाद शीर्ष न्यायालय ने ही कारिडोर बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया है। यहां का गोस्वामी समाज कारिडोर निर्माण के विरोध में आंदोलनरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए मंदिर कोष के उपयोग की अनुमति भी दी है। यह शर्त है कि जमीन की रजिस्ट्री बांकेबिहारी के नाम से होनी चाहिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर सेवायतों की याचिका पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है, इसलिए इसमें अभी कुछ और फैसले आने बाकी हैं। सरकार की परिकल्पना मंदिर क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के प्रवेश के लिए मार्ग चौड़ीकरण के साथ उन्हें पार्किंग सुविधा प्रदान करने की है।

प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के योगी सरकार के प्रयास और इससे उपजे विश्वास से प्रदेश की छवि बेहतर बनी है। पहले भी लोग आते थे, पर धार्मिक स्थलों के बहुविध विकास से अब इनके अधिक संख्या में आने की आश्वस्ति डग भरने लगी है। काशी-अयोध्या का धार्मिक पर्यटन से बड़ा प्रकल्प और क्या हो सकता है। संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए भी माहौल बना है। सांसद हेमा मालिनी मानती हैं कि ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग का विकास भी आवश्यक है और यह गति नहीं पकड़ रहा है। उनका मानना है कि अलीगढ़ और मथुरा के जनप्रतिनिधि ही अड़ंगा लगा रहे हैं। मथुरा के साथ ही परिक्रमा मार्ग का कुछ हिस्सा राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी आता है। समग्र विकास से नई भाव भूमि बनेगी।

छत्तीसगढ़ डायरी

नेताम के बहाने मतांतरण और माओवाद की चर्चा

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

रायपुर के सिविल लाइंस स्थित इंडियन काफी हाउस में लगभग 80 वर्षीय बुजुर्ग को अकेले काफी पीते देख किसी को भी यह भ्रम हो सकता था कि इस उम्र में भरी दोपहरी संभवतः अकेलापन दूर करने यहां पहुंचे होंगे। वर्ष 2023 में गर्मी के ही महीनों की बात है। आते जाते लोग नमस्कार करते हुए बढ़ जा रहे थे। फुसफुसाहट भी थी, पांच बार सांसद रहे अरविंद नेताम की यह स्थिति है। सच में समय बलवान होता है। बोधघाट परियोजना में आदिवासियों के हितों की रक्षा के मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विवाद के बाद नेताम हाशिए पर चले गए थे। उसी वर्ष राजनीतिक जीवन से संन्यास की घोषणा भी कर दी। अब पांच जून को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 'कार्यकर्ता विकास वर्ग' में शामिल होने के बाद फिर चर्चा के केंद्र में हैं। साथ ही, उनका यह चिंतन भी विरोधियों को बेचैन कर रहा है कि 'मतांतरण और माओवादियों की समस्या के समाधान के लिए आदिवासी समाज और संघ को मिलकर काम करना होगा।'

यह संयोग ही हो सकता है कि सीएम विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मंत्रणा के बाद पिछले 40 वर्षों से अटकी बोधघाट बांध परियोजना के फिर शुरू होने की शनिवार को ही घोषणा की है। महानदी और इंद्रावती नदी को जोड़ने की परियोजना भी शुरू होगी। लगभग सात लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा के लिए इन दोनों योजनाओं पर 49 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। विपक्ष को इसी बात का ज्यादा गुस्सा है कि नेताम के विरोध के कारण ही बघेल के कार्यकाल में यह काम नहीं शुरू हो सका था और अब नेताम संघ एवं भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं। संघ के कार्यक्रम में नेताम के शामिल होने के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजियों का तीखा दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आदिवासियों के हितों को संघ और भाजपा के हवाले करने का आरोप लगाया तो नेताम ने उलटा पूछ लिया कि बैज को स्पष्ट करना चाहिए कि वह आदिवासी हैं या मतांतरित ईसाई? भड़के कांग्रेसी बैज के दंतेश्वरी माता का भक्त होने का दावा कर रहे हैं।

बेटी डा. प्रीति नेताम के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (दाएं) से मिलते अरविंद नेताम। डीपीआर

इधर नागपुर संघ कार्यालय के अनुभव को आधार बनाकर नेताम बहुत स्पष्ट हो चुके हैं कि संघ को बाहर से नहीं समझा जा सकता। विरोधी दलों द्वारा फैलाए गए भ्रम के पीछे भय है। बस्तर में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से संघ के कार्यकर्ता तो 1952 से ही आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, घर वापसी और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करने में जनजाति सुरक्षा मंच, राष्ट्रीय सेवा भारती, सामाजिक एकता मंच, एकल विद्यालय, क्रीड़ा भारती जैसी संघ की अन्य आनुषंगिक इकाइयां भी सक्रिय हैं। नेताम के संरक्षण वाला सामाजिक संगठन, सर्व आदिवासी समाज इन संगठनों का हर स्तर पर विरोध करता था। अब बदले हुए नेताम का मानना है कि संघ शुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और वह स्वयं भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए संघ हर स्तर पर काम कर रहा है तो कांग्रेस हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखती है, इसलिए पार्टी की दुर्गति हो गई है।

कांग्रेसी पृष्ठभूमि वाले आदिवासी नेता अरविंद नेताम एमए और एलएलबी की डिग्री के बाद मात्र 29 वर्ष की उम्र में बस्तर की कांकेर सीट से 1971 में सांसद बने तो इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री भी बन गए। वर्ष 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी वह मंत्री रहे। वर्ष 1997 से 2023 के बीच चार बार कांग्रेस छोड़ने का कारण वह पार्टी की व्यवस्था में दम घुटना बताते हैं। इस दौरान वह बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी, भाजपा और जय छत्तीसगढ़ पार्टी का हिस्सा बने। नेताम मानते हैं कि संघ ने समाज के बीच उनके 60 वर्षों के काम को मान्यता देते हुए नागपुर बुलाया। कांग्रेस में एक परिवार के बाहर ऐसा संभव नहीं होता। नेताम की यही टिप्पणियां कांग्रेसियों को परेशान कर रही हैं, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक के रूप में उन्होंने पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर काम किया। बस्तर में माओवादी आतंकियों का अंत करीब माना जा रहा है, परंतु आदिवासियों को संस्कृति से दूर करने के लिए मतांतरण में जुटे संगठनों का प्रभाव काफी बढ़ चुका है। ऐसे में नेताम की चिंता को गंभीरता से लेना होगा कि माओवादियों और मतांतरण की समस्या से निपटने के लिए आदिवासी समाज और संघ को एकजुटता से काम करना ही होगा। उम्मीद की जा रही है कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं की चर्चा और बयानबाजी सभी सत्यों और तथ्यों को सतह पर लाएगी।

****

अमेरिका का दोहरा रवैया

भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में शीत युद्ध के दौर का गहरा असर रहा है। उस दौर में भारत सोवियत संघ के करीब था, वहीं पाकिस्तान अमेरिका का करीबी सहयोगी था। सोवियत संघ के विघटन के बाद बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत-अमेरिका के बीच संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के संबंध रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर हैं। इसके बावजूद भारत-अमेरिका के रिश्तों में वह भरोसा और स्थायित्व नहीं दिखता है, जो रूस और भारत के रिश्तों में है। इसकी वजह अमेरिका का दोहरा रवैया है। हाल में भारत आए अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने आपसी संबंधों को लेकर शिकायत की थी कि भारत रूस से हथियार खरीदता है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखे। लेकिन वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं करता है और पाकिस्तान को समय-समय पर हथियार व वित्तीय मदद भी देता है। पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। भारत-अमेरिका के रिश्तों में इस विरोधाभास की पड़ताल ही अहम मुद्दा है...

इलस्ट्रेशन अवधेश

कम्युनिस्ट चीन का दिया साथ

"अमेरिका का कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं है, केवल हित हैं।

अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक है।"

-हेनरी किसिंजर, पूर्व विदेश मंत्री, अमेरिका

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन कर उभरा। दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ था। तब से अब तक अमेरिका की विदेश नीति को इन दो प्रसिद्ध कोट के दायरे में देखा जा सकता है। एक समय अमेरिका कम्युनिस्ट चीन को सोवियत संघ का सहयोगी और अपने लिए खतरा मानता था, लेकिन 1967 में रूस और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर लड़ाई हुई। इससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता आ गई। अमेरिका को यह मौका मुफीद लगा और उसने सोवियत संघ के प्रभाव को कमजोर करने के लिए चीन के साथ अपने संबंध सुधारे। अमेरिका ने कहा कि एक समृद्ध चीन दुनिया के हित में होगा। चीन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से तकनीक, निवेश मिला। चीन के युवाओं को अमेरिका और दुनिया के दूसरे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिला। चीन ने इस मौके का फायदा उठाया और आज चीन 20 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है।

तालिबान का पितामह है अमेरिका

अमेरिका अपने हितों के लिए किस हद तक जा सकता है। इसका एक दूसरा बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान का तालिबान है। सोवियत संघ की सेनाएं 1979 में कम्युनिस्ट सरकार के समर्थन में अफगानिस्तान में घुसी थीं। अमेरिका ने सोवियत संघ को हराने के लिए स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों और पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को प्रशिक्षण और हथियार दिए। बाद में इन्हीं मुजाहिदीन ने काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इनको आज दुनिया तालिबान के नाम से जानती है। यही वह दौर था जब पाकिस्तान ने इस्लामी आतंकवाद को पालना पोसना शुरू किया और बाद में इनका इस्तेमाल एक नीति के तहत भारत के खिलाफ किया। आतंक का यह इकोसिस्टम पाकिस्तान में आज भी मजबूत है और भारत पर लगातार हमले कर रहा है।

भारत का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका

अमेरिका को एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की जरूरत है। चीन एक जटिल पड़ोसी है। 2020 में गलवन में चीन और भारत की सेनाओं के बीच घातक झड़प हो चुकी है। उस समय अमेरिका ने सेटेलाइट और दूसरी खुफिया मदद भी भारत को मुहैया कराई थी। ऐसे में भारत को भी चीन के खिलाफ संघर्ष की सूरत में अमेरिका की जरूरत है। समस्या यह है कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। खास कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में। इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका की पहल पर क्वाड नामक संगठन भी बना है। इसमें अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान के साथ भारत भी है। चीन इसे अपने खिलाफ खेमेबंदी के तौर पर देखता है। हालांकि, भारत क्वाड को सैन्य गठबंधन का रूप देने के खिलाफ रहा है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्ता के साथ सहज नहीं अमेरिका और पश्चिमी देश

भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की नीति अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुभ रही है। रणनीतिक स्वायत्ता का मतलब है कि भारत खुद को किसी खेमे में नहीं बांधेगा और अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से सभी देशों से बात करेगा। 2024 में रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भारत के रवैये पर आपत्ति जताते हुए भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा था कि संघर्ष के दौरान रणनीतिक स्वायत्ता नाम की कोई चीज नहीं होती है। संकट के समय भारत और अमेरिका को विश्वसनीय सहयोगी की तरह मिलकर काम करना चाहिए। रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान अमेरिका और यूरोप इस बात से असहज थे कि भारत ने रूस के हमले की निंदा नहीं की और वह उससे तेल खरीद रहा है। अमेरिका को भारत और रूस के रक्षा संबंधों से भी दिक्कत है।

पाकिस्तान में मिला ओसामा बिन लादेन

2001 में अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पूरी दुनिया में खोजता रहा। आखिरकार 11 वर्ष के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में खोजा और उसका खात्मा किया। पाकिस्तान वही देश है जो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का करीबी साथी होने का दावा करता है। अमेरिका और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि लादेन पाकिस्तान की सरकार और सेना के संरक्षण के बिना वहां छुपा नहीं रह सकता था, लेकिन अमेरिका सब कुछ जान कर भी चुप रह गया। इसकी वजह यह है कि उसे अपने हितों के लिए पाकिस्तान की जरूरत है और वह पाकिस्तान की सरकार व सेना को इस्तेमाल कर सकता है। इस लिहाज से पाकिस्तान उसके लिए मुफीद देश है।

रक्षा आपूर्ति में विविधता लाया है भारत

34% रह गई है भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी, पहले 70 प्रतिशत थी

20 अरब डालर से अधिक कीमत के रक्षा उपकरण खरीदे हैं भारत ने अमेरिका से पिछले दो दशक में

फ्रांस, इजरायल और दूसरे देशों से भी हथियार खरीद रहा है भारत

रक्षा खरीदारी का गणित

अमेरिका से रक्षा खरीदारी में चुनौतियां	रूस क्यों है भरोसेमंद
अमेरिका के रक्षा उपकरण बहुत महंगे हैं	रक्षा उपकरण किफायती हैं
हथियारों के साथ शर्त लगाता है	बिना शर्त हथियार देता है
तकनीक साझा नहीं करता है	संयुक्त उत्पादन का विकल्प देता है
बात न मानने पर रोक सकता है सप्लाई	आपूर्ति के मामले में अब तक भरोसेमंद

लंबी अवधि में मजबूत बनी रहेगी रणनीतिक भागीदारी

अमेरिका का यह तर्क ठीक नहीं है कि भारत रूस से रक्षा उपकरण खरीदता है तो इससे अमेरिका को दिक्कत होती। अमेरिका से रिश्ते बनाने का यह सही तरीका नहीं है। वैश्विक बाजार में रूस भी हथियार बेचता है और अमेरिका भी हथियार बेचता है। दूसरे देश भी हैं। भारत अपने हितों के हिसाब से रूस से हथियार खरीदता है। यहां यह भी अहम बात है कि भारत अमेरिका से भी अरबों डालर के हथियार खरीदता है। अगर अमेरिका यह चाहता है कि भारत रूस से अपने ऐतिहासिक और मजबूत रक्षा संबंध तोड़ कर रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए, तो ऐसी गलती भारत शायद ही करे। भारत ने पिछले एक दशक में एक नीति के तहत अपने रक्षा आयात में विविधता का समावेश किया है। आज भारत सिर्फ रक्षा आपूर्ति के लिए सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है। वह रूस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, इजरायल सहित दूसरे देशों से रक्षा उपकरण खरीद रहा है। जहां तक आपसी रिश्तों में संवेदनशीलता की बात है तो ट्रंप प्रशासन आज रूस का समर्थन कर रहा है और युद्ध के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बता रहा है। वास्तव में आज तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति नहीं आया है और आगे शायद ही कोई उनकी तरह आए। ट्रंप को भू राजनीतिक जटिलताओं का अनुभव नहीं है। वह हर चीज को आर्थिक फायदे के लिहाज से देखते हैं, लेकिन वैश्विक कूटनीति में चीजें इस तरह से नहीं

चिंतामणि महापात्र
संस्थापक, कलिंगा इंस्टीट्यूट आफ इंडो पैसिफिक स्टडीज

> ट्रंप 2.0 में भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव का यह दौर अस्थायी है। कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग का तंत्र विकसित हो चुका है। यह सहयोग साझा हितों पर आधारित है। ऐसे में लंबी अवधि में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत बने रहेंगे।

चलती हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों में आए विरोधाभास अस्थाई हैं। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका की नीतियों के बारे में कुछ भी भरोसे नहीं कहा जा सकता है। ट्रंप ऐसा सिर्फ भारत के साथ नहीं कर रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में अमेरिका को लेकर भरोसे का स्तर इस समय निचले स्तर पर है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी नाटो की आलोचना की थी और कहा कि उनको गठबंधन की जरूरत नहीं है। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे सही किया। यह एक अस्थाई दौर है। लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो भारत और अमेरिका रणनीतिक भागीदार हैं और यह भागीदारी आगे भी जारी रहने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को लेकर यूरोप भी बहुत असहज है। यूरोप अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था। यूरोप अमेरिका के हर सही गलत काम का समर्थन करता रहा है। आज ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं आपको अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे में वर्तमान समय में वर्ल्ड आर्डर में बदलाव हो रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका लंबे समय तक दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रहा है, लेकिन चीन के उभार के बाद चीजें बदल गई हैं। भारत भी दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर भी उभर रहा है। दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है। अमेरिका अब भी दुनिया की महाशक्ति है, लेकिन अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है। ट्रंप की नीतियों से वैश्विक स्तर पर अमेरिका का प्रभाव और भी कम होने की आशंका है। अगर ट्रंप की टैरिफ नीतियां कारगर साबित नहीं हुईं तो अमेरिका को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव होगा बल्कि भारत जैसे देशों का महत्व बढ़ेगा। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के मद्देनजर यूरोप सहित दूसरे देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह ट्रंप की नीतियों से पैदा हुई अनिश्चितता का ही नतीजा है।

समय के साथ बदलते रहते हैं राष्ट्रीय हित

डा. अभिषेक श्रीवास्तव
असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएनयू

> अमेरिका और भारत के रिश्ते सिर्फ साझा हितों के आधार पर विकसित हुए हैं, लेकिन दोनों देशों के हित हमेशा मेल खाएं यह जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय हित कई कारकों पर निर्भर करते हैं और इनमें समय पर बदलाव आता रहता है।

अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी विदेश नीति में काफी बड़े बदलाव कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से भारत – अमेरिका संबंध बेहतर हो रहे हैं। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना खुद अमेरिका के हित में है और यह अमेरिकी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह भारतीय विदेश नीति की अनदेखी ना करे। अमेरिका आतंरिक संकटों से गुजर रहा है तथा अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप अपनी कई नीतियों को लागू करने में असमर्थ दिख रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर देशों के बीच मूल्य आधारित सहयोग को सीमित करना या उसे कमजोर करना अमेरिकी नेतृत्व पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है।

हालांकि यह कहना कि अमेरिका भारत के हितों को नजरअंदाज करके द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है, यह जल्दबाजी होगी। कुछ मामलों में, अमेरिका भारत के साथ अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर दे सकता है, लेकिन यह हमेशा भारत के हितों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खा सकता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, चीन का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत साझेदारी चाहता है, लेकिन वह भारत के लिए अपनी सुरक्षा एवं रणनीतिक हितों के लिहाज से भी आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो शीत-युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ इस क्षेत्र में पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था। 1987 में अमेरिका ने पाकिस्तान को गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था, जो आज भी जारी है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा प्राप्त होना तथा तुर्की जैसे देशों का नाटो का सदस्य होना वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी नीति पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

शीत युद्ध के बाद के युग में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। दोनों देशों के रिश्ते अलगाव से जुड़ाव में बदल गए। इस बदलाव के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारक थे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के प्रति अपनी नीतियों को नया आकार दिया है। अमेरिका ने भारत के साथ एक समावेशी आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक साझेदारी विकसित की, और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक विस्तारवादी नीतियों ने दोनों दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया है। भारत और अमेरिका अब हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और एशिया में पर्याप्त शक्ति संतुलन बनाए रखने में साझा हित रखते हैं। आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति हिंद महासागर से तय होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थवाद से ज्यादा प्रभावित होती है। ऐसे में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बहुलवाद और विविधता जैसे हमारे साझा मूल्य पर्याप्त नहीं होते, कई बार विरोधाभासी हो सकते हैं। राष्ट्रीय हित कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमे समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। यदि सिर्फ मूल्य आधारित रिश्ते अहमियत रखते तो दोनों देश वर्षों पहले ही गठबंधन बना लेते या साझेदार हो गए होते। इतिहास हमें सिखाता है कि रिश्तों के विकास के लिए ये मूल्य न तो आवश्यक हैं और न ही पर्याप्त हैं, बल्कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं।

वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज करना या अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी खतरों पर एक स्वर में जवाब ना देना दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को नुकसान पहुंचा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका की पाकिस्तान-नीति उसके "ग्लोबल वार आन टेरर" की भावना के विपरीत दिखती है। अमेरिका अपने हितों के लिए अवसरवाद को अपनाता रहता है। भारत के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ-साथ अन्य देशों के साथ भी एक मजबूत साझेदारी बनाए। भारत की स्वतंत्र तथा स्वायत्त विदेश नीति पर निर्भर है कि वह अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को कैसे आगे बढ़ाए। भारत को अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी के फायदे और नुकसान दोनों पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके आधार पर आगे का रास्ता तय करना होगा।

आपकी आवाज

जी हां। यह कटु सत्य है कि अमेरिका जैसे 'बिन पेंदी के लोटे' पर भरोसा करना भारत के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अमेरिका स्वार्थी और अवसरवादी देश है। भारत को अमेरिका के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए बेहद सतर्क रहना होगा। **-आंनिका सेतिया**

ट्रंप के लिए द्विपक्षीय रिश्ते मायने नहीं रखते हैं उनके लिए बस आर्थिक लाभ मायने रखता है। ट्रंप कारोबारी रहे हैं और दिक्कत यह है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर भी सिर्फ मुनाफे के लिए काम करना चाहते हैं। वह यह नहीं समझ रहे हैं कि राजनय और कारोबार में फर्क है। यही वजह है कि वह भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौल रहे हैं। **-राजेश चौहान**

भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अमेरिका या कोई भी देश उसे नजर अंदाज नहीं कर सकता है। मित्र देश के तौर पर अमेरिका का ट्रैक रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में हमें अमेरिका से मित्रता की उम्मीद न रख कर आपसी हितों के आधार पर द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। **-मनोज वर्मा**

राष्ट्रीय फलक

हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ेगा पर्यटकों का ठहराव, पर्यटन होगा सुदृढ़

- सीमावर्ती शिपकी ला गांव से कल सीमा पर्यटन की शुरुआत
- चीन सीमा तक जाने की अनुमति मिलने से किन्नौर में पांच दिन तक घूम सकेंगे पर्यटक

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला

हिमाचल के सीमावर्ती गांव में पर्यटन गतिविधियां शुरू होने से पर्यटकों का प्रदेश में ठहराव बढ़ेगा। इससे जनजातीय पर्यटन सुदृढ़ होगा। चीन की सीमा तक जाने की अनुमति मिलने से किन्नौर जिले में तीन से पांच दिन तक पर्यटक घूमने का आनंद ले सकेंगे। अभी तक पर्यटक सीमावर्ती क्षेत्रों से 50 किलोमीटर पीछे तक ही जा सकते थे। 10 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीमावर्ती शिपकी-ला गांव से 'सीमा पर्यटन' की शुरुआत करेंगे। इससे देशभर के पर्यटकों को किन्नौर और लाहुल स्पीति जिलों के भारत चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा।

पर्यटकों को हिमाचल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लेपचला, शिपकी ला, ग्यू मठ, खाना डुमटी, सांगला, रानी कंडा, छितकुल तथा लाहुल स्पीति के चयनित क्षेत्रों तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा अनूठी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना हैं। भारत-चीन की सीमा से सटे इन क्षेत्रों में विशेष अनुमति लेकर जाना पड़ता था लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल बना दी गई है। नए निर्देश के अनुसार स्थानीय निवासी और प्रमाणित पर्यटक अब वैध पहचानपत्र दिखाकर इन स्थानों पर जा सकते हैं। आइटीबीपी और सेना निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी।

> सीमावर्ती क्षेत्रों तक जाने की अनुमति से पर्यटकों के ठहराव के दिनों में वृद्धि होगी। पर्यटन शहरी क्षेत्रों के बजाय दूरदराज क्षेत्रों में निकलना चाहता है। अब चीन की सीमा तक जाने की व्यवस्था होने से पर्यटक किन्नौर में अधिक दिन गुजारते हुए लाहुल-स्पीति की ओर बढ़ेंगे और लेह तक पूरा 10 दिन या इससे अधिक दिन का पैकेज लेकर निकलेंगे।
>
> -महेंद्र सेठ, अध्यक्ष, होटल एंड रेस्तरां स्टेकहोल्डर एसोसिएशन

भागवत ने कहा-मंदिर, जलाशय और श्मशान पर समाज का समान अधिकार

- पूर्वी क्षेत्र के शिक्षा वर्ग में पहुंचे संघ प्रमुख ने की पंच परिवर्तन पर चर्चा
- स्वयंसेवकों से जातिवाद खत्म करने के लिए प्रयास करने का किया आह्वान

जागरण संवाददाता, कानपुर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने एक बार फिर स्वयंसेवकों के बीच पंच परिवर्तन की चर्चा की। स्वयंसेवकों से चर्चा के दौरान उन्होंने जातिवाद को खत्म करने का आह्वान किया। कहा कि मंदिर, जलाशय और श्मशान पर संपूर्ण समाज का एक समान अधिकार होना चाहिए।

संघ प्रमुख भागवत पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग में सुबह और शाम की शाखा में भी स्वयंसेवकों के साथ रहे। एक अलग तरीके के समाज की परिकल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम संघ के शताब्दी वर्ष में हैं। पंच परिवर्तन के आधार पर संपूर्ण समाज को बड़े परिवर्तन की ओर जाने का प्रयास हो रहा है।

एक ऐसा समाज जो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व के लिए भी जागरूक हो। ऐसा समाज जो पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करे। शिक्षार्थियों के साथ उनका सत्र आपसी संवाद का रहा। न्होंने शिक्षार्थियों से बातचीत में उनके कार्य क्षेत्र में संघ के चल रहे कार्य, शाखाओं, सेवा कार्य के बारे में जानकारी ली। आह्वान किया कि शाखा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार तक स्वयंसेवकों का संपर्क होना चाहिए। संघ प्रमुख सोमवार रात 9.57 बजे कानपुर सेंट्रल से तेजस राजधानी ट्रेन से पटना के लिए रवाना होंगे।

डा. मोहन भागवत फाइल

****

स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम नहीं

नागपुर, एएनआइ : मोहन भागवत ने कहा कि देश की स्वतंत्रता 1857 के विद्रोह से शुरू हुए व्यापक प्रयासों का परिणाम है। यह किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। नागपुर में कहा कि हमेशा यह बहस का मुद्दा होता है कि देश को स्वतंत्रता किसके प्रयासों से मिली। वास्तविकता यह है कि यह स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति के कारण नहीं मिली। इसके लिए प्रयास 1857 में शुरू हुआ जो निरंतर चलता रहा। सभी के सामूहिक प्रयासों से ही हमें स्वतंत्रता मिली। किसी भी चीज की दिशा सामूहिक विचार से तय होती है। यह एक या दो लोगों का कार्य नहीं है। संघ जो भी करता है वह सामूहिक निर्णय होता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में एक बर्बर हमला हुआ। आतंकियों ने हमारे हमारे नागरिकों की हत्या की। सभी की इच्छा थी कि आतंकियों को सजा मिले। इसी के अनुरूप कड़ी कार्रवाई भी हुई।

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई

लखनऊ में रविवार को समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी सगाई के दौरान। इस समारोह में दोनों के स्वजन, करीबी रिश्तेदार, मित्र और सपा के कई नेता शामिल हुए। रिंकू और प्रिया की शादी 18 नवंबर को वाराणसी में होनी है। प्रेट

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 9 जून, 2025

दैनिक जागरण
जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं नहीं

तीसरे कार्यकाल का पहला साल

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष जैसे राजनीतिक वातावरण में पूरा होने जा रहा है, वह इसलिए अधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि जब इस सरकार ने अपनी तीसरी पारी शुरू की थी तब राजनीतिक माहौल बिल्कुल विपरीत था। ऐसा इसलिए था, क्योंकि भाजपा अपने बलबूते बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी और उसे सरकार गठन के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा था। इसके चलते यह माना गया कि मोदी सरकार अपने पहले और दूसरे कार्यकाल की तरह बड़े और साहसिक फैसले नहीं ले पाएगी और उसे कई विषयों पर गठबंधन के घटक दलों और विशेष रूप से जदयू और तेलुगु देसम के दबाव-प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। एक साल के कार्यकाल ने इस धारणा को ध्वस्त करते हुए यही स्पष्ट किया कि भाजपा भले ही 240 सीटों तक सीमित रही हो, लेकिन मोदी सरकार अपने एजेंडे को लागू करने के लिए पहले की ही तरह प्रतिबद्ध है। इसका एक बड़ा उदाहरण वक्फ संशोधन विधेयक को कानून का रूप देना है। भाजपा सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर वक्फ कानून में संशोधन के अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी और उसे पूरा भी कर दिखाया। इसी तरह वह लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि देश को अगले वर्ष मार्च तक माओवाद से मुक्त करा लिया जाएगा।

मोदी सरकार किस तरह साहसिक फैसले लेने में समर्थ है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपरेशन सिंदूर। पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों की ओर से 26 लोगों की जघन्य हत्या के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह पहले पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया और फिर उसके कई प्रमुख एयरबेस ध्वस्त कर दिए, वह सचमुच अकल्पनीय सैन्य कार्रवाई है। मोदी के नेतृत्व वाला भारत ऐसी कठोर कार्रवाई करेगा, इसकी कल्पना न तो पाकिस्तान ने की होगी और न ही विश्व समुदाय ने। मोदी सरकार ने देश और दुनिया को दिखाया कि भारत को आतंकवाद से लड़ना आता है। इसका एक और प्रमाण पाकिस्तान से किए गए सिंधु जल समझौते को स्थगित करना भी है। तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होते-होते जिस तरह यह खबर आई कि भारत पिछले 11 वर्षों में 27 करोड़ लोगों को अति निर्धनता से उबारने में सफल रहा, वह इस सरकार की विकास और जनकल्याणकारी नीतियों की सफलता का ही परिचायक है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने ही वाला है। इस सबका यह मतलब नहीं कि मोदी सरकार के समक्ष कहीं कोई चुनौती नहीं है और देश सभी समस्याओं से मुक्त हो चुका है, लेकिन इतना तो है ही कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस को इस सरकार की रीति-नीति की आलोचना करते समय अपने घनघोर नकारात्मक रवैये का परित्याग करना होगा।

क्रूरता की हद

पति-पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास, सम्मान और साथ पर आधारित होता है। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को समझना, राय का सम्मान करना और एक-दूसरे को खुशी देना आवश्यक है। लेकिन हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग में एक घटना ने इस रिश्ते की गरिमा को तार-तार कर दिया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को न केवल प्रताड़ित किया, बल्कि उसे जंजीरों से बांधकर घर में बंधक बना लिया। यह घटना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह समाज में बढ़ती विकृत मानसिकता का भी संकेत देती है। यह सवाल उठता है कि पति-पत्नी के बीच इस तरह की परिस्थितियां कैसे और क्यों उत्पन्न हुईं? इस तरह की घटनाएं न केवल पीड़ित महिला के लिए, बल्कि समाज के लिए भी चिंताजनक हैं। पति-पत्नी का रिश्ता नाजुक होता है, जिसे देखभाल और समझ के साथ बनाए रखना आवश्यक है। कई बार कुछ कारणों से रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन यह स्थिति कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे को प्रताड़ित करने लगे। यह न केवल रिश्ते की गरिमा को गिराता है, बल्कि समाज में महिला सशक्तीकरण के दावों को भी धक्का पहुंचाता है। महिलाओं के प्रति इस तरह के अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए समाज को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति की अस्मिता के साथ इस तरह से खेलना न केवल गलत है, बल्कि यह सभ्य समाज के लिए भी शर्मनाक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिले और उनके साथ खड़े होने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। हमें एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा मिले। हमें अपने आस-पास की स्थितियों को गंभीरता से लेना होगा। एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देना होगा।

विश्वास के संकट से घिरी न्यायपालिका

हृदयनारायण दीक्षित

विचारणीय प्रश्न है कि भ्रष्टाचार में प्रथमदृष्टया लिप्त पाए गए न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए सत्ता पक्ष को क्यों विवश किया जा रहा है?

भारतीय न्यायपालिका विश्वास के संकट से गुजर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की घटनाओं से जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे पूरी न्याय प्रणाली में विश्वास कम हो सकता है।' यह गंभीर बात उन्होंने तब कही है, जब भ्रष्टाचार के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग पर सत्ता पक्ष विपक्षी दलों से विचार विमर्श कर रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने बीते दिनों कहा था कि 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सरकार न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के महाभियोग प्रस्ताव पर सभी दलों का सहयोग चाहती है।' उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने भी वर्मा को दोषी ठहराया है।

देश में न्यायिक सुधारों की मांग काफी पुरानी है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। न्यायिक सुधारों की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था, पर जजों की नियुक्ति की उस प्रणाली को न्यायपालिका द्वारा निरस्त कर दिया गया था। कहा गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारिक लक्षण है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने भी कहा है कि 'वर्तमान कोलेजियम प्रणाली आलोचना से रहित नहीं है, पर इसका समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं हो सकता।' न्यायिक स्वतंत्रता की बात ठीक है, संवैधानिक है, पर न्यायपालिका सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं द्वारा मर्यादा पालन जरूरी है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कदाचरण के प्रश्न लगातार उठते रहे हैं। न्यायमूर्तियों के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई जटिल है। संविधान के अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर कार्रवाई के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदन के सदस्यों का सामान्य बहुमत और वोट डालने वाले उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत अनिवार्य है। इसके पूर्व लोकसभाध्यक्ष/सभापति एक जांच समिति गठित करते हैं। इस जांच के बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है।

न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में लोकसभा में पहला महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन अपेक्षित बहुमत के अभाव में गिर गया। 2011 में कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने राज्यसभा द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर त्यागपत्र दे दिया था। 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश जे. पारदीवाला के विरुद्ध आरक्षण संबंधी आपत्तिजनक बयान पर महाभियोग का नोटिस दिया था। उसी साल लगभग 50 राज्यसभा सदस्यों ने न्यायमूर्ति एसके गंगेले के विरुद्ध नोटिस दिया था। उन पर जिला जज के यौन उत्पीड़न का आरोप था। जजेज इंक्वायरी एक्ट (1968) के अधीन जांच कमेटी बनाई गई थी। प्रस्ताव पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गया। 2017 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के न्यायमूर्ति सीवी नागार्जुन रेड्डी के विरुद्ध भी राज्यसभा सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव रखा था। 2018 में विपक्षी दलों ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के विरुद्ध भी महाभियोग के प्रस्ताव का प्रयास किया था। सिक्किम हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पीडी दिनाकरन के विरुद्ध आए प्रस्ताव पर राज्यसभा के सभापति ने आरोप जांचने के लिए समिति गठित की थी। दिनाकरन ने इसी दौरान त्यागपत्र दे दिया।

अवधेश राजपूत

भारतीय संविधान के प्रवर्तन के 75 वर्ष के भीतर महाभियोग के सिर्फ पांच प्रस्ताव सिद्ध करते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया बहुत जटिल है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए विशेष सुरक्षा कवच उपलब्ध कराए हैं। कायदे से न्यायपालिका को स्वयं अपने तंत्र के भीतर भ्रष्टाचार और लोक शिकायतों की जांच का कोई ढांचा विकसित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संविधान निर्माता स्वतंत्र न्यायपालिका एवं सबको न्याय की गारंटी चाहते थे। संविधान सभा में (छह जून, 1949) सी. दास ने कहा था, 'विश्वास है कि डा. आंबेडकर एवं सदन के अन्य विधि विद्वान ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसमें लोगों को न्याय मिले।' सभा में सुप्रीम कोर्ट के कार्य आवंटन पर बहस चल रही थी। दास ने कहा, 'मेरे मित्र ब्रिटिश प्रणाली के न्याय निर्वचन पर क्यों मुग्ध हैं? प्रस्तावित उपबंधों के अनुसार एक न्यायालय से दूसरे एवं अंत में सर्वोच्च न्यायालय में अपील जाएगी। ऐसी हालत में जनसाधारण को न्याय कैसे मिलेगा?' न्याय सबकी अभिलाषा थी और है। सभा में एम. थीरुमल राव ने कहा, 'न्यायालयों का जाल बिछ गया है, लेकिन इन न्यायालयों में वही जा सकते हैं जो संपन्न हैं।'

संप्रति न्यायिक प्रक्रिया बहुत महंगी है। संपन्न के लिए सर्वसुलभ है और गरीबों के लिए महादुर्लभ है। यह स्थिति उस देश की है, जहां हजारों वर्ष पहले भी सर्वसुलभ राजव्यवस्था एवं न्यायव्यवस्था थी। ऋग्वेद के रचनाकाल में 'ग्राम्यवादिन' न्याय की छोटी इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश को स्थपति बताया गया है। बुद्ध काल की न्याय व्यवस्था बहुत लोकप्रिय थी। चंद्रगुप्त मौर्य (320 ईस्वी) के कार्यकाल में ग्राम न्यायालय, जनपद न्यायालय एवं केंद्रीय न्यायालय थे। गुप्त काल (पांचवीं सदी) की प्रशंसा में चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है कि 'कानून सरल और उदार थे। अपराधों की गुह्यता के आधार पर दंड व्यवस्था है।' आखिरकार चूक कहां हो रही है? निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमों का अंबार है। विचारणीय प्रश्न है कि भ्रष्टाचार में प्रथमदृष्टया लिप्त पाए गए न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए सत्ता पक्ष को क्यों विवश किया जा रहा है? ज्यादातर मामलों में उच्च अदालतें यही वाक्य दोहराती हैं कि सरकारें अपना काम नहीं करतीं तो क्या हम चुप बैठें। यहां स्थिति उल्टी है। सरकार अपना पूरा काम करने को तत्पर है और न्यायपालिका मौन है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं)
response@jagran.com

सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अमृतकाल

स्वामी अवधेशानंद गिरि

विविधताओं के उत्सव से राष्ट्रीयता का जो अमृत निकल रहा है, वह भारत को अनंतकाल तक ऊर्जावान रखेगा

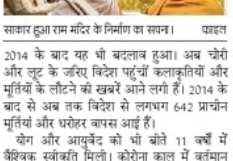

वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ देश में सकारात्मक परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो कार्य प्रारंभ हुआ, उसे जारी रहते हुए 11 वर्ष हो गए। ये 11 वर्ष भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की न केवल नींव बने, बल्कि भारत की संस्कृति को जीवंतता भी प्राप्त हुई। इस सबका केंद्र बिंदु है भारतीय संस्कृति और विरासत को सहेजने एवं संवारने के प्रति प्रधानमंत्री का समर्पण। उनके कार्यकाल में हमारी महान धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार कर उसे पुरानी गरिमा वापस दिलाने का भगीरथ प्रयास हुआ है। 'विरासत भी, विकास भी' जैसे दृष्टिकोण के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ध्वजा फहरा रही है।

मैं अक्सर चिंतन करता था कि अहिल्याबाई होलकर की तरह क्या कोई हमारी महान सांस्कृतिक चेतना को फिर से प्रतिष्ठित करने में सहायक होगा? रामलला का अपने घर विराजमान होना, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं महाकाल लोक कारिडोर का निर्माण, सोमनाथ मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार, करतारपुर साहिब कारिडोर तैयार होना, चार धाम परियोजना का विकास, बुद्ध एवं जैन सर्किट के निर्माण के जरिए मोदी सरकार ने न केवल देश की सांस्कृतिक विरासत को एकसूत्र में पिरोया, बल्कि उसे अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ गर्व से खड़ा होना भी सिखाया। वर्षों बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ जम्मू-कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन हुआ। दशम गुरु गोबिंद सिंह के सुपुत्रों के बलिदान को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा भी बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक रही। हमारी विदेश नीति में भी देश के सांस्कृतिक महत्व को स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री विदेशी अतिथियों को श्रीमद्भगवद्गीता जी, तुलसी जी का पौधा या भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजें भेंट करते हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन और उसके पहले इस समूह की देश भर में आयोजित बैठकों में हमने दुनिया को अपनी संस्कृति से परिचित कराया। वर्षों से देश से सैकड़ों प्राचीन की मूर्तियां और कलाकृतियां चोरी करके विदेश भेजी जाती रही हैं। हम ऐसे समाचार पढ़ते थे, लेकिन कभी मूर्तियों की वापसी की खबरें देखने-पढ़ने को नहीं मिलती थीं।

साकार हुआ राम मंदिर के निर्माण का सपना। फाइल

2014 के बाद यह भी बदलाव हुआ। अब चोरी और लूट के जरिए विदेश पहुंचीं कलाकृतियों और मूर्तियों के लौटने की खबरें आने लगी हैं। 2014 के बाद से अब तक विदेश से लगभग 642 प्राचीन मूर्तियां और धरोहर वापस आई हैं।

योग और आयुर्वेद को भी बीते 11 वर्षों में वैश्विक स्वीकृति मिली। कोरोना काल में वर्तमान पीढ़ी ने आयुर्वेद के महत्व को और अच्छे से समझा। इस बार 21 जून को हम 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यह विशेष गर्व की अनुभूति वाला क्षण है, क्योंकि योग दिवस को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रधानमंत्री की पहल से ही मिली। देश में गोवंश की महत्ता फिर से स्थापित हुई है। डिजिटल इंडिया अभियान के साथ सांस्कृतिक डाक्यूमेंटेशन का भी अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। 'राष्ट्रीय सांस्कृतिक डिजिटल डाटाबेस' के माध्यम से दो लाख से अधिक सांस्कृतिक संस्थाओं और विरासत स्थलों का डिजिटल रिकार्ड तैयार किया गया है। एक भारत-श्रेष्ठ भारत, काशी- तमिल संगमम, सौराष्ट्र-तमिल संगमम और विरासत का उत्सव जैसे अभियानों से सांस्कृतिक एकता मजबूत करने का प्रयास किया गया है। संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थलों के आधुनिकीकरण का भी प्रयास हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव संग्रहालय तैयार किया गया है। लगभग 500 से अधिक स्मारकों का संरक्षण किया गया है।

प्रधानमंत्री ने विदेश में बसे भारतीय प्रवासियों को सांस्कृतिक राजदूत बनने की प्रेरणा दी और आह्वान किया कि वे भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाएं। विविधताओं के इन उत्सवों से राष्ट्रीयता का जो अमृत निकल रहा, वह भारत को अनंतकाल तक ऊर्जावान रखेगा। सनातन संस्कृति और उसकी आत्मा क्या है? अखंड भारत का विचार क्या है? भारत अनेकता में एकता का देश कैसे है और पूरा देश एक सूत्र में कैसे पिरोया हुआ है? इस सबका दर्शन हमें पूर्ण महाकुंभ में मिला। प्रयागराज में मुझे दिव्य ऊर्जा का जो आभास हुआ, उससे यह विश्वास हो गया कि इस देश की आध्यात्मिक चेतना को कोई डिगा नहीं सकता। यह ऐसा आयोजन था, जो यदि न हुआ होता तो दुनिया नहीं मानती कि ऐसा आयोजन हो भी सकता है।

आपरेशन सिंदूर की भी चर्चा आवश्यक है। हमारी पराक्रमी सेनाओं ने आतंकवाद को जैसा करारा जवाब दिया, उसने दुनिया में भारत की नई पहचान को प्रतिष्ठित किया। न्याय की अखंड प्रतिज्ञा के विचार तले आपरेशन सिंदूर के महानायकों को नमन। बीते 11 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत मंडपम और नया संसद भवन बनते देखा। संसद में सेंगोल स्थापित होते और जलियांवाला बाग का पुनरुद्धार होते भी देखा। हमने डिफेंस कारिडोर बनते देखा तो चिनाब पर सबसे ऊंचा रेल पुल भी। हम 'मेक इन इंडिया' के साथ 'मेड इन इंडिया' के साक्षी भी बने। हम 'नमामि गंगे' की धार बने तो नारी शक्ति वंदन और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के कारक भी। हम स्वच्छ भारत की संस्कृति के पालनकर्ता भी बने तो प्रमुख आर्थिक शक्ति भी अर्थात विरासत भी, विकास भी।

(लेखक जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अंतर्मन से संवाद

संसार में व्याप्त माया के प्रभाव और विकारों से ग्रस्त मानव मन प्रायः किसी न किसी प्रश्न पर व्यथित होता रहता है। मन को शांत और आश्वस्त करने के लिए मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार भिन्न-भिन्न उपाय करता है। दुख है तो सुख प्राप्ति का प्रयास करता है। निराशा है तो आशा का भाव दृढ़ करता है। रोग है तो निरोग होने का प्रयास करता है। इस तरह मनुष्य ने हर विषमता का एक विकल्प खोज लिया है, ताकि मन स्थिर हो सके। इससे क्षणिक लाभ भले प्राप्त हो जाए, पर व्यग्रता बनी ही रहती है। जैसे सुख प्राप्त कर लिया है तो सुख के बने रहने और निरोग है तो सदा निरोग रहने की चिंता करता है। मन को शांत करने के ये समस्त उपाय एक तरह से सच से पलायन करने जैसा है। जीवन की सार्थकता विकल्पों में नहीं, संकल्पों में है। दुख का विकल्प सुख नहीं है। दुख तब दूर होता है जब उसे सीधे संबोधित किया जाए। दुख क्यों है इसका कारण मन जानता है। मन ही इसका समाधान भी जानता है।

एक मन ही है, जो मनुष्य के पल-पल का हाल जानता है। मन ही ऐसा मित्र है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो सच्चा मार्गदर्शक है। मनुष्य जब भी मन के निकट गया है उसे राह मिली है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जो उसका अपना निवास स्थान है। विडंबना यह है कि मनुष्य सारे विश्व का भ्रमण कर लेता है, किंतु अपने मन के द्वार को ही दस्तक देना भूल जाता है जहां उसकी गति है। वह किसी से भी किसी भी भाषा में घंटों संवाद कर सकता है, किंतु अपने मन की भाषा से ही अनभिज्ञ है। इसीलिए मन से संवाद नहीं हो पाता। यह भाषा है सत्यनिष्ठा की। सत्यनिष्ठ भाव से मनुष्य जब अपने मन से दुख का कारण पूछेगा तो उसे सच्चा उत्तर मिलेगा, जिसमें निदान भी निहित होगा। मनुष्य के प्रत्येक दुख के पीछे उसका कोई न कोई विकार है। उस विकार पर अंकुश प्राप्त करना ही दुख से उबरना है।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

हवा में मौजूद डीएनए में जीवन के सुराग

मुकुल व्यास

हवा में भी डीएनए मौजूद होता है, जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हवा में भी डीएनए मौजूद होता है, जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में किए गए एक अध्ययन में विज्ञानियों ने पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की आनुवंशिक सामग्री को शहर के वातावरण में बहते हुए पाया। इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने शहर की हवा में अवैध नशीली दवाओं के निशान भी खोजे। आसपास के वातावरण में मौजूद आनुवंशिक सामग्री को पर्यावरणीय डीएनए या एनवायरनमेंटल डीएनए (ईडीएनए) कहा जाता है। हवा में मौजूद डीएनए में जीवन के सुराग छिपे हैं।

फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में वन्यजीव रोग विज्ञान के प्रोफेसर डेविड डफी पिछले काफी समय से ईडीएनए का अध्ययन कर रहे हैं। उनकी टीम ने सबसे पहले पानी, रेत और मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करके समुद्री कछुओं की आबादी का अध्ययन करने के लिए ईडीएनए उपकरण विकसित किए थे। डफी ने कहा कि पर्यावरणीय डीएनए में उपलब्ध जानकारी के स्तर को देखते हुए हमने मनुष्यों, वन्यजीवों और अन्य प्रजातियों में इसके संभावित अनुप्रयोगों के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में स्थित एक प्रयोगशाला ने हवा सहित लगभग हर वातावरण से डीएनए निकालने और उसका विश्लेषण करने के अपने तरीकों को व्यापक बनाया है। यह डीएनए केवल सतह पर नहीं रहता, बल्कि हवा में भी स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि घंटों या कई दिनों तक चलने वाले साधारण एयर फिल्टर बड़ी मात्रा में सूचनात्मक आनुवंशिक सामग्री एकत्र कर सकते हैं। इस विधि से एक क्षेत्र में सभी प्रजातियों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। डफी की प्रयोगशाला ने डबलिन में हवाई डीएनए संग्रह उपकरण स्थापित किए। उपकरण के फिल्टर ने शहर की हवा में तैर रहे सैकड़ों मानव रोगाणुओं के निशान एकत्र किए, जिनमें वायरस और बैक्टीरिया शामिल हैं। इस तरह की निगरानी बीमारी के प्रकोप का जल्दी पता लगाने या आबादी के माध्यम से फैलने वाले संक्रमण को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

इस तरीके से मौजूदा तकनीकों की तुलना में पर्यावरणीय एलर्जी का भी अधिक सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। एलर्जी का पता लगाने की क्षमता डाक्टरों द्वारा रोगियों को सलाह देने के तरीके या सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा चेतावनी जारी करने के तरीके को बदल सकती है। डफी की टीम ने फ्लोरिडा के जंगलों में भी अपनी विधि का परीक्षण किया। वहां एयर फिल्टर ने छोटे जीव-जंतुओं के डीएनए के नमूने एकत्र किए। खास बात यह थी कि डीएनए ने न केवल इन जानवरों की उपस्थिति का पता लगाया, बल्कि यह भी बताया कि वे कहां से आए थे। विज्ञानियों का कहना है कि इस तरह की सटीकता से जानवरों के संरक्षण के लिए बेहतर उपाय खोजने में मदद मिल सकती है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

मेलबाक्स

इस्लाम को बदनाम करते कट्टरपंथी

'मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद मानवता, शांति, विकास और लोकतंत्र जैसे मूल्यों का शत्रु है, तथा एक ऐसे सोच का परिणाम है, जो सिर्फ विनाश, भय और नफरत को जन्म देता है। यह तथ्य केवल इस्लामी जगत एवं विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को ही विचलित करने वाला नहीं है, बल्कि विश्व के समस्त विद्वत समाज को भी विचलित और चौकन्ना करता है। पहलगाम हमले के बाद टीवी पर दिखाए गए एक कार्यक्रम में एक पाकिस्तानी से उस घटना पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उसका उत्तर था, 'सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से यह हत्या गलत थी, किंतु मजहबी दृष्टि से यह सही थी, क्योंकि एक गैर मुस्लिम की हत्या से आतंकियों को सबाब (पुण्य) मिला।' कुरान शरीफ के 114 में से 113 परिच्छेदों में अल्लाह की असीमित दया एवं उपकारशीलता का उल्लेख मिलता है। उसकी दया और क्षमाशीलता के उल्लेख बार-बार मिलते हैं। 78 आयतों वाला 55वां सूरा, जिसे सूरा रहमान कहा जाता है, पूरा का पूरा अल्लाह के दयाभाव पर आधारित है। यह असंभव सा लगता है कि अल्लाह के पैगंबर ने अपने मजहब में आतंकवाद के घुसने की कोई इजाजत दी होगी। ऐसा लगता है कि बाद में अनेक मुसलमानों ने सत्ताप्राप्ति के लिए आतंकवाद का सहारा लिया और इस्लाम को बदनाम किया। वे घोषणा करते हैं कि जब तक पूरी धरती उनके कब्जे में नहीं आ जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अर्थात आतंकवाद पर लगाम नहीं लग पाएगी। यह सुखद है कि पूरी मानव जाति के सुख एवं कल्याण के लिए कमर कसे भारत की अगुआई में सारा विश्व एकजुट होकर धरती से आतंकवाद को पूर्णतया समाप्त करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ नजर आ रहा है।

डा. बलराम मिश्र, इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र दिल्ली के पूर्व प्रमुख, लखनऊ

एक और उपलब्धि

किसी भी विकासशील देश की गरीबी 'गरीबी हटाओ' जैसे राजनीतिक नारे से नहीं मिट सकती। इसके लिए साफ-सुथरी नियत के साथ जनकल्याणकारी कारगर योजनाएं बनाई जाती हैं। फिर उनके धरातल तक क्रियान्वयन की भ्रष्टाचार मुक्त ठोस रणनीति बनानी पड़ती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 से 2023 के बीच करीब 27 करोड़ लोगों का अति गरीबी रेखा की निर्धनता से मुक्त होना विकसित भारत की प्रथम सीढ़ी मानी जा सकती है। विकास योजनाएं पहले भी बनती थीं, लेकिन तब कारगर रूप से धरातल तक नहीं पहुंच पाती थीं। ऊपर से नीचे तक व्याप्त आर्थिक भ्रष्टाचार के चलते बिचौलिए इन विकास योजनाओं की राशि को बीच में ही हड़प कर जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। जन-धन योजना के अंतर्गत खुलवाए गए देश के गरीबों के जीरो बेलेंस बैंक खातों के माध्यम से अब उनके हिस्से की सरकारी धनराशि शत-प्रतिशत रूप से उनको प्राप्त होने लगी है। अन्य विकास योजनाओं का क्रियान्वयन भी धरातल तक होने लगा है। इन सबका प्रभाव देश की निर्धनता उन्मूलन में देखने को मिला और आज विश्व बैंक की रिपोर्ट के रूप में हकीकत सब के सामने है।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़ (उप्र)

एक खटासभरा रिश्ता

डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच मतभेद उभरने लगे हैं। हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की कंपनियों टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ सरकारी अनुबंधों में कटौती की घोषणा की। इसके जवाब में एलन मस्क ने धमकी दी कि वह ड्रैगन कैप्सूल की सेवा बंद कर सकते हैं। यह कैप्सूल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य सामग्री को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मस्क की यह तकनीक नासा के अंतरिक्ष अभियानों की रीढ़ बन चुकी है। इसके अलावा, नासा ने कई सैन्य अभियानों में भी स्पेसएक्स की मदद ली है। ट्रंप के नए विधेयक से टेस्ला को नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसलिए मस्क ने अब उनसे दूरी बना ली है।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर/चीफ एग्जीक्यूटिव- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 09-06-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH12 User: dilip.lal Time: 06-08-2025 22:19 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 9 जून 2025

देर आए, दुरुस्त आए

कनाडा को आखिरकार G7 सम्मेलन के लिए भारत को न्योता देना पड़ा। यह नई दिल्ली के बढ़ते वैश्विक कद को दिखाता है। भारत को साथ लिए बिना दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों के लिए भी अपने अजेंडे पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा।

दूसरे देशों का दबाव । कनाडा के पीएम मार्क कार्नी पर खालिस्तान समर्थक संगठनों का बेहद दबाव था कि उसकी अध्यक्षता में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रित न किया जाए। कार्नी सरकार ने शुरुआत में अलगाववादियों की मांग के सामने लगभग हथियार डाल ही दिए थे, लेकिन उनके बयान से जाहिर है कि मंच के बाकी सदस्य देश भारत की भागीदारी चाहते थे और इसके चलते कनाडा को झुकना पड़ा। उस पर यह प्रेशर भी होगा कि मेजबान होने के नाते अगर सम्मेलन सफल नहीं रहता है, तो जवाबदेही उस पर आएगी।

G7 का भारत को न्योता

दुनिया के हित में । कार्नी ने खुद स्वीकार किया है कि एनर्जी, AI, अहम खनिजों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सबसे प्रभावशाली देशों को आमंत्रित करना जरूरी है। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी आबादी होने के नाते भारत का इस सम्मेलन में होना स्वाभाविक है। यह नई दिल्ली नहीं, इस मंच और बाकी दुनिया के हित में है कि भारत इसका हिस्सा बने।

भारत का बड़प्पन । कनाडा ने आखिरी वक्त पर भारत को आमंत्रित किया, वह भी इस मुद्दे पर उठे विवाद के बाद। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार किया और कार्नी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। यह भारत के जिम्मेदारी भाव और बड़प्पन को दर्शाता है कि कूटनीतिक तकाजों से अलग उसने हालात के मुताबिक फैसला लिया।

अलगाववादियों पर एक्शन । पीएम मोदी ने अपने मेसेज में कहा है कि भारत और कनाडा आपसी सम्मान व साझा हितों के मार्गदर्शन में मिलकर काम करेंगे। इसके मायने हैं कि भारत पिछली कड़वाहट को भुलाकर कनाडा के साथ संबंध सुधारने को तैयार है, लेकिन क्या कार्नी सरकार भी तैयार है? इसके लिए उसे अपने यहां मौजूद कट्टरपंथी और अलगाववादी तत्वों के प्रेशर से बाहर निकलना होगा।

फायदा उठाए कनाडा । भारत को बुलाना भले कनाडा की मजबूरी रही हो, लेकिन अब उसके पास इस अवसर का फायदा उठाने और अपनी गलती सुधारने का मौका है। पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के दौर में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर के चलते जो रिश्ता बिगड़ गया, कनाडा अब उसे सुधार सकता है।

चक्र-व्यू

इमाम पसंद आम

राहुल पाण्डेय

आम फलों का राजा है, मगर फलों के राजा में भी कई और राजा होते हैं। पिछले हफ्ते घर में इसी राजसी खानदान के सिरमौर कहे जाने वाले इमाम साहब पधारे। मैं इन्हें इमाम साहब कहता हूं, कोई इन्हें इमाम पसंद कहता है तो कोई हिमाम पसंद या हिमायत। आए तो राजा साहब पिछले साल भी थे, लेकिन इस बार हमने इनका स्वागत कुछ खास तरीके से किया। पर इससे पहले कि स्वागत-सत्कार की ओर आगे बढ़ें, इमाम साहब की खासियत जान लें। यह दक्षिणी भारत में आमों के शहंशाह कहे जाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में इनका राज है। सर्च करने पर पता चला कि इनकी कलम अब उत्तर भारत में लगाने के लिए भी मुहैया है। कहते यह भी हैं कि साहब मूलरूप से केरल की पैदाइश हैं और मुगल शहंशाह हुमायूं के दिल के खासे करीब थे। अब चूंकि राजा साहब हैं तो भारी-भरकम होंगे ही। इमाम पसंद के एक नग का वजन आधा किलो से लेकर 800 ग्राम तक हो सकता है। बाज दफे एक किलो तक भी पहुंच जाता है। बात शक्ल-ओ-सूरत की करें तो इनकी सूरत काफी कुछ अपने यहां आम के सीजन के अंत में आने वाले जंगली आम से मिलती है। बस जंगली आम का छिलका मोटा होता है, तो इमाम साहब की त्वचा जरा सी खुरचने पर रस बरसाने लगती है।

इमाम साहब का स्वागत हमने धूपबत्ती से किया। भगवान की अटारी से उठाकर गेंदे के दो फूल भी ससम्मान भेंट किए। एक बार में एक तिहाई आम काटा गया। कहने को तो इमाम पसंद साउथ के आमों के शहंशाह हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके स्वाद में भारत भर की तासीर है। पहला टुकड़ा मुंह में रखते ही पहला स्वाद अपने गांव के देसी आमों की आई। लगा कि सीधे गुड़िया बुआ के बाग में आम भरी बाल्टी लेकर बैठे हों। देसी आमों की खासियत होती है कि उनका स्वाद और महक कुछ चरपरापन लिए होती है, शायद चोपी की वजह से। लेकिन इमाम पसंद की महक छोड़ दें तो इसके स्वाद में तनिक भी चरपरापन नहीं था। बल्कि यह कहना गैर-मुनासिब न होगा कि स्वाद में यह हापुस से भी अधिक मीठे और चौसे से भी अधिक गूदेदार थे। इन्हें खाना गांव के बाग में वापस पहुंचकर कभी खटहवा चुलमुलाना है, कभी सिपिहवा टॉफी की तरह मुंह में रखकर मुलमुलाना है। अब राजा साहब को काटकर फ्रिज में रख दिया है। जब भी बाग में पहुंचकर बचपन में जाना होता है, इमाम साहब से गूदे भर का इनाम ले लेता हूं।

एकदा

कन्नड़ में हंसी

20वीं सदी में कन्नड़ भाषा के विख्यात उपन्यासकार और लेखक हुए - शिवराम कारंत। यह बात उन दिनों की है, जब वह हाई स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने नियम बना रखा था कि बड़ी कक्षा के विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे। वह चाहते थे कि सभी छात्रों की अंग्रेजी भाषा पर गहरी पकड़ हो। प्रधानाचार्य जिसे भी कन्नड़ भाषा में बात करते देख लेते, उसे सजा देते थे। कारंत को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह मातृभाषा कन्नड़ से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन प्रधानाचार्य कहीं गए हुए थे। शिवराम कारंत और दूसरे स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। कारंत ने वहां अपने साथियों से कोई बात मजाकिया अंदाज में कही, जिसे सुनते ही सभी छात्र हंसने लगे। कारंत ने बनावटी गुस्से में साथियों को जोर से डांटते हुए कहा, 'फूल, हाउ डू यू लाफ इन कन्नड़? यू आर अ हाई स्कूल स्टूडेंट, लाफ इन इंग्लिश।' तीर ठीक निशाने पर लगा। प्रधानाचार्य समझ चुके थे कि कारंत क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने फिर कभी किसी छात्र को कन्नड़ में बात करने पर दंडित नहीं किया। उसी शिवराम कारंत को बाद में साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संकलन : दीनदयाल मुरारका

सरकार ने कई ऐसे फ़ैसले लिए, जो भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए

कास्ट सेंसस, महिला आरक्षण होंगे बड़े मुद्दे

नीरजा चौधरी

नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, अब 11वां साल चल रहा है। भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ही थीं, जो लंबे समय तक सत्ता में रहीं, लेकिन उनके कार्यकाल में भी बीच में रुकावट आई थी। नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री यह लगातार तीसरा कार्यकाल है।

जनाधार बढ़ाया । मोदी सरकार की सफलता को चार बड़े कारणों से समझा जा सकता है। पहला, हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की छवि। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी की 'हिंदू हृदय सम्राट' की छवि बनी। लेकिन इसमें सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों को भी शामिल किया गया। खासकर OBC और दलित समुदायों को अपनी ओर खींचने में मोदी ने महारत हासिल की। BJP, जो पहले ब्राह्मण-बनिया आधारित पार्टी मानी जाती थी, अब OBC और दलितों तक अपनी पहुंच बढ़ा चुकी है। हाल ही में सरकार ने कास्ट सेंसस का फैसला लिया, जो इस दिशा में एक और कदम है।

कई सफलताएं
- दलितों और OBC को BJP ने जोड़ा
- सरकारी पैसा सीधे लोगों के खाते में
- PMO हुआ अधिक शक्तिशाली

समाज कल्याण योजनाएं । दूसरा कारण है सामाजिक कल्याण योजनाएं। मोदी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू कीं, जिनसे सीधे लोगों के खातों में पैसा पहुंचा। आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना, पेंशन स्कीम्स और मुफ्त राशन जैसी पहल ने गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाया। यही वह नींव है, जिसने BJP को एक व्यापक जनाधार दिया।

कमजोर विपक्ष । तीसरी वजह है मजबूत नेतृत्व। गांव-गांव में लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं। इस छवि ने उन्हें विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद की। और, चौथा कारण है विपक्ष की कमजोरी। विपक्ष का एकजुट न होना मोदी की राह को आसान बनाता है। 2024 के चुनावों में भले ही विपक्ष ने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी एकजुटता और रणनीति में अभी भी कमी दिखती है।

बड़े फैसले । मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए, जो भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। आर्टिकल 370 को हटाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि, विपक्ष इसे लागू करने के तरीके से सहमत नहीं रहा। ट्रिपल तलाक खत्म करना और राम मंदिर का निर्माण भी मोदी सरकार के कोर अजेंडे का हिस्सा रहे। ये वे मुद्दे हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में अधूरे रह गए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सरकार धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

विदेश नीति पर सवाल । विदेश नीति में मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल-पार्टी डेलिगेशन ने भारत की एकजुटता को दुनिया के सामने पेश किया। इसके बावजूद कुछ सवाल उठे हैं। पाकिस्तान के साथ चीन, अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों का खड़ा होना और भारत के सबसे पुराने मित्र रूस का भी सीजफायर के लिए ट्रंप को श्रेय देना विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं।

पावरफुल PMO । मोदी सरकार की सबसे बड़ी आलोचना अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ती असुरक्षा को लेकर है। 20 करोड़ मुसलमानों को लगता है कि उनका भविष्य अनिश्चित है। तीसरे टर्म में उन्हें सुरक्षित महसूस कराना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं जैसे CBI, ED आदि का दुरुपयोग किया। PMO का अति शक्तिशाली होना भी एक सवाल है। इंदिरा गांधी के दौर में भी PMO मजबूत था, लेकिन मोदी सरकार में इसे 'प्रेसिडेंशियल स्टाइल' गवर्नेंस कहा जा रहा है।

आज की चुनौतियां । तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। 2024 के चुनावों में BJP को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके अलावा, विपक्ष ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। खासकर यूपी में विपक्ष ने OBC और दलित वोटरों को अपनी ओर खींचा। 2014 में यूपी ने BJP को 71 लोकसभा सीटें दी थीं, 2019 में 65 सीटें मिलीं, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा घटकर 33 पर पहुंच गया। यह उसके लिए बड़ा झटका था।

आगे की राह । 2027 में यूपी और गुजरात के चुनाव BJP के लिए अहम होंगे। कास्ट सेंसस और विमिन रिजर्वेशन बिल जैसे कदम 2029 के लोकसभा चुनावों में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन हाइपर-नैशनलिज्म और गठबंधन की राजनीति को संतुलित करना आसान नहीं होगा। खासकर तब, जब RSS और BJP के भीतर से भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। मोदी का व्यक्तित्व और उनका नैरेटिव अभी भी जनता को आकर्षित करता है। लेकिन तीसरे कार्यकाल में एंटी-इनकंबेंसी, आर्थिक चुनौतियां, और गठबंधन की मांगें उनके बड़े इम्तिहान हैं। जाहिर है, गवर्नेंस में नयापन लाना, सहयोगियों को साथ बनाए रखना और अपनी मजबूत छवि को बरकरार रखना आसान नहीं होगा।

(लेखिका राजनीतिक विश्लेषक हैं)

मोदी
मोदी सरकार के 11 साल

मोदी की तीसरी पारी तक क्या-क्या बदला

हिलाल अहमद

इतना आसान नहीं है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल का आकलन करना। इसका कारण है हमारे सार्वजनिक विमर्श में गहरा राजनीतिक विभाजन। एक ओर मोदी समर्थक हैं, जो इस काल खंड को स्वतंत्र भारत का स्वर्ण युग मानते हैं और मनवाना चाहते हैं। दूसरी ओर एक तबका है, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात बिगड़ने का जिम्मेदार सिर्फ BJP सरकार को ठहराता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम राजनीतिक-बौद्धिक खेमेबंदी को दरकिनार करके विश्लेषण के ऐसे मापदंड चुनें, जिनके जरिए पिछले 10 सालों में हुए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की शोधपरक समीक्षा की जा सके।

तीन मापदंड । मेरे विचार से तीन ऐसे मापदंड हैं- राज्य का बदलता चरित्र, राजनीतिक अस्तित्व के बुनियादी सवालों का उभरना और राष्ट्र व राष्ट्रीयता की पुनर्व्याख्या। पिछले 10 सालों में राज्य का चरित्र मौलिक रूप से बदल गया है। इसे अब लोकहितकारी या वेलफेयर स्टेट कहना उचित नहीं है। इसे खैराती राज्य या चैरिटेबल स्टेट कहा जा सकता है।

दोनों मॉडल में फर्क । लोकहितकारी राज्य नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है और कल्याणकारी योजनाएं नागरिकों का अधिकार होती हैं। लेकिन खैराती राज्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन को अलग-अलग करके देखता है। राज्य का खैराती मॉडल इस मान्यता पर टिका है कि प्रतियोगी बाजार अपने आप को सुचारू रूप से चला सकता है, इसलिए उसके परिचालन मे राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए।

बाजार की खातिर । यह राज्य नागरिकों की क्षमता बढ़ाने के लिए वन-टाइम योजनाएं, जैसे उज्ज्वला या प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करता है। इन योजनाओं का मकसद नागरिकों को इतना सक्षम बनाना है कि वे बाजार की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। इस तरह, कल्याणकारी कार्यक्रम खैरात की तरह दिए जाते हैं, न कि अधिकार के रूप में।

बुनियादी सवाल उभरे । पिछले 10 सालों में कई ऐसे मुद्दे उठे हैं, जिन्हें पहले स्थापित और अछूता माना जाता था। नागरिकता, चुनाव, जनगणना, राष्ट्रीय चिह्न और स्मारक- ये सभी अब संशय के दायरे में हैं। उदाहरण के लिए, एक देश-एक चुनाव की बहस ने चुनाव के स्थापित स्वरूप की प्रासंगिकता पर सवालिया निशान लगा दिया है। दूसरी ओर जाति जनगणना की बहस ने आरक्षण और सामाजिक न्याय के स्वीकार्य ढांचे पर नए सवाल उठाए हैं। सबसे दिलचस्प बदलाव राष्ट्रीय चिह्नों और स्मारकों में देखने को मिला है।

वॉर मेमोरियल । इंडिया गेट पर बने नैशनल वॉर मेमोरियल ने नए राजकीय रिवाजों की शुरुआत की है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देकर एक नई परंपरा शुरू की थी। अब मोदी सरकार ने नैशनल वॉर मेमोरियल के जरिए इसे एक नया स्वरूप दिया है। इसका सीधा मतलब है कि राजनीतिक अस्तित्व के बुनियादी सवाल अब नए अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। ये बदलाव न सिर्फ प्रतीकात्मक हैं बल्कि इनसे भारतीय समाज की सोच भी बदल रही है।

नई अवधारणाएं
- वेलफेयर स्टेट बदला खैराती मॉडल में
- राष्ट्रीय चिह्नों व स्मारकों में भी बदलाव
- राष्ट्र व राष्ट्रीयता की बदली परिभाषा

राष्ट्र और राष्ट्रीयता । राष्ट्र और राष्ट्रीयता की परिभाषा में आया बदलाव इस युग का सबसे बड़ा परिवर्तन है। योगेंद्र यादव ने अपने हालिया लेखों में तर्क दिया है कि भारतीय राष्ट्रवाद एक सकारात्मक राष्ट्रवाद रहा है, जो यूरोप के एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति वाले राष्ट्रवाद से अलग था। भारतीय संविधान विविधता को भारत की ताकत मानता है। लेकिन हाल के वर्षों में राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना उभरी है, वह एकता की बजाय एकरूपता को तरजीह देती सी लगती है। यह वह परिकल्पना है, जिसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने खारिज किया था। क्या भारत अपनी विविधता को बनाए रख पाएगा, या वह एकरूपता की ओर बढ़ेगा? यह सवाल न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

नए सवालों का दौर । मोदी युग के आकलन के लिए हमें उन बुनियादी सवालों पर ध्यान देना होगा, जिन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को बदला है। खैराती राज्य की अवधारणा ने कल्याणकारी राज्य की जगह ले ली है। नागरिकता, चुनाव और राष्ट्रीय चिह्न जैसे मुद्दों पर नए सवाल उठे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रवाद की परिभाषा में बदलाव ने भारत की मूल पहचान को चुनौती दी है।

फिर से सोचें । इन तीन मापदंडों के आधार पर हमें पिछले 10 सालों का विश्लेषण करना चाहिए। इस तरह का विश्लेषण न केवल हमें इस काल खंड मे अपनाई गई नीतियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बदलावों को बेहतर तरीके से समझने मे मदद करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी।

(लेखक CSDS में प्रोफेसर हैं, विचार निजी हैं)

सोशल जस्टिस : सपना हो रहा साकार

डॉ. वीरेंद्र कुमार

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आज 11 साल पूरे हो रहे हैं। विगत 11 वर्षों का यदि ट्रैक रेकॉर्ड देखा जाए, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिये वंचित वर्ग की अस्मिता और स्वाभिमान को सुदृढ़ किया है। पिछड़ा, दलित और आदिवासी अस्मिता की इस नीति का ध्येय वाक्य है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।'

आज 11 वर्षों के सुशासन के बाद यह कहा जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे NDA सरकार पूरा कर रही है। जातिगत जनगणना का निर्णय पिछड़ा, दलित और आदिवासियों के अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पिछले 11 वर्षों में, मुख्य रूप से उपेक्षित और ग्रामीण पृष्ठभूमि से 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुई हैं। लखपति दीदी कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक 1.25 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाने वाली ड्रोन चलाने वाली महिलाओं ने महिलाओं के बारे में समुदाय की धारणा बदल दी है।

मोदी सरकार के स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत बैंक की प्रत्येक ब्रांच अपने क्षेत्र के एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को लोन देगी। इसके तहत 2.5 लाख दलित उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सामाजिक न्याय हमारी सरकार के लिए सिर्फ कहने-सुनने की बात नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है, हमारी श्रद्धा है। इसी को पूरा करते हुए उन्होंने 2020 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एससी/एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

2014 में आरंभ किए गए प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। इसके तहत जनजातीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और संचार समेत 14 क्षेत्र निर्धारित किए गए। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना की स्थापना की गई है। वर्ष 2026 तक देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है।

उपलब्धियों की राह
- सवा करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई गईं
- ढाई लाख दलित उद्यमी तैयार किए जा रहे
- 2026 तक बनेंगे 728 एकलव्य मॉडल स्कूल

2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का विस्तार करते हुए इसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना है। मोदी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थों- जन्मस्थान महू, दीक्षा स्थल नागपुर, चैतन्य भूमि भूमि इंदु मिल मुंबई, शिक्षा भूमि लंदन और महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली में स्मारकों के निर्माण व जीर्णोद्धार की पहल की। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब दिया गया, जब केंद्र में बीजेपी समर्थित वी पी सिंह की सरकार थी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं बल्कि सबकी साझेदारी, सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी नीति को भी प्रतिबिंबित भी कर रही हैं।

(लेखक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं)

व्यक्तित्व का प्रभाव शब्दों और विचारों से ज़्यादा

स्वामी विवेकानंद

अपने चारों ओर जो हो रहा है उसे आप अच्छी तरह देख रहे हैं। संपूर्ण विश्व प्रभावात्मक है। हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर के पोषण में व्यय होता है उसे छोड़ बाकी बची हुई संपूर्ण शक्ति दूसरों को प्रभावित करने में ही लगती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारी बुद्धि और हमारी आध्यात्मिकता - सभी निरंतर दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यही क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती है।

एक व्यक्ति आपके पास आता है, वह विद्वान है, उसकी भाषा बड़ी मधुर है। वह काफी देर तक आप से वार्तालाप भी करता है, पर आपके ऊपर प्रभाव जमाने में वह असफल रहता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति आता है, जो अपनी टूटी-फूटी भाषा में कुछ ही शब्द बोल पाता है, फिर भी वह आप पर विशेष प्रभाव जमा जाता है। इससे स्पष्ट है कि केवल शब्दों से प्रभाव नहीं जमता। शब्द और विचार दोनों मिलकर किसी दूसरे पर प्रभाव जमाने के कार्य में केवल एक तिहाई अंश का काम देते हैं, बाकी दो तिहाई तो व्यक्तित्व ही काम देता है। व्यक्तित्व में वह आकर्षण-शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव जमाती है। हम लोगों के घरों में भी मुखिया होते हैं, पर सभी मुखिया कुटुंबियों पर प्रभाव डालने में सफल नहीं होते। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल। ऐसा क्यों? हम लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जब हमें असफलता मिलती है, तो हम कह उठते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारी असफलता के कारण हैं। असफलता में कोई अपना दोष या अपनी कमजोरी स्वीकार करना नहीं चाहता।

प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष समझता है और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी असफलता का कारण बताता है। जब कुटुंब के मुखिया अपनी व्यवस्था में असफल हों तो उन्हें स्वयं अपने से ही प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। बीते हुए समय के बड़े-बड़े लेखकों और विचारकों को लें और देखेंगे कि उन्होंने भी वास्तव में कितना सोचा है। उन सारे प्राचीन लेखकों का व्यक्तित्व ही काम देता है। उनकी पुस्तक को सामने रख कर उसका मूल्य आंके तो हमें पता लगेगा कि इस जगत में नए और मौलिक विचार बहुत ही कम हैं। उनकी पुस्तकों में दिए गए विचारों का अध्ययन करें तो वे लेखक हमारे लिए बहुत महान नहीं ज्ञात होते, पर हम यह भी जानते हैं कि वे अपने युग में महान थे। किस चीज ने उन्हें इतना महान बनाया था?

उन्हें महान बनाने का श्रेय न उनके विचारों को है, न उनके ग्रंथों को है और न उनके व्याख्यानों को ही। वह तो कुछ दूसरी ही वस्तु थी और चली गई - वह था उनका व्यक्तित्व।

('मन की शक्तियां' पुस्तक से)

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ आम लोगों को राहत

7 जून का संपादकीय 'ग्रोथ पर दांव' पढ़ा। रेपो दरों में आधा फीसदी की कटौती तो विशेषज्ञों ने भी अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन महंगाई में कमी और मजबूत आर्थिक सूचकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह निर्णय लेने में मदद की। इससे आम लोगों को बहुत फायदा होगा जो अपने घर के लिए लोन लेना चाहते हैं। अब घर लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेश्यो में भी 1 फीसदी की कटौती की है जिससे 5 लाख करोड़ रुपये बैंकिंग सिस्टम में उपलब्ध हो जाएंगे और कॉरपोरेट जगत को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण लेने में आसानी होगी।

बाल गोविंद, नोएडा

■ ट्रंप की साख

डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर जितने धमाकेदार ढंग से दूसरी बार काबिज हुए थे, उससे ऐसा लगा था कि उनका दूसरा कार्यकाल अमेरिका की साख को दुनिया भर में और मजबूती देगा। लेकिन ट्रंप ने ऐसा ड्रामा शुरू किया कि नजदीकी मित्र और सहयोगी अरबपति इलॉन मस्क भी उनके विरोधी बन गए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जो भद पिट चुकी है, वह तो वापस नहीं होने वाली।

अरविंद रावल, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

राहुल बोले, महाराष्ट्र चुनावों में हुई थी मैच फिक्सिंग- एक खबर

- मैच के बाद फिक्सिंग का रोना काम नहीं आता।

प्रीतम झा